arihant

संशोधित संस्करण

बैंकिंग जागरूकता

बैंकिंग जागरूकता • वित्तीय जागरूकता
भारतीय अर्थव्यवस्था • वित्तीय एवं बैंकिंग करेण्ट अफेयर्स

- अध्यायवार पाठ्य-सामग्री
- अध्यायवार अभ्यास प्रश्न
- विगत 10 वर्षों (2020-11) की परीक्षा के प्रश्न
- 3 प्रैक्टिस सेट्स

IBPS & SBI PO/Clerk/RRB
तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

₹ बजट 2021-22 के साथ...

बैंकिंग
जागरूकता

बैंकिंग जागरूकता • वित्तीय जागरूकता
भारतीय अर्थव्यवस्था • वित्तीय एवं बैंकिंग
करेण्ट अफेयर्स

IBPS & SBI PO/Clerk/RRB
तथा अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

संकलनकर्ता
राकेश कुमार रोशन

arihant
अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड

arihant

अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड

सर्वाधिकार सुरक्षित

卐 **© प्रकाशक**

इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके—इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से प्रकाशक की अनुमति के बिना वितरण नहीं किया जा सकता है। 'अरिहन्त' ने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए प्रकाशक, सम्पादक, लेखक अथवा मुद्रक जिम्मेदार नहीं हैं।

सभी प्रतिवाद का न्यायिक क्षेत्र 'मेरठ' होगा।

卐 **रजि. कार्यालय**

'रामछाया' 4577/15, अग्रवाल रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली- 110002
फोन: 011-47630600, 43518550

मुख्य कार्यालय

कालिन्दी, टी०पी० नगर, मेरठ (यूपी)– 250002
फोन: 0121-7156203, 7156204

卐 **शाखा कार्यालय**

आगरा, अहमदाबाद, बरेली, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, झाँसी, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर तथा पुणे

卐 **ISBN** 978-93-25797-34-5

卐 **PO No :** ₹XT-XX-XXXXXXX-X-XX

PUBLISHED BY ARIHANT PUBLICATIONS (INDIA) LTD.

'अरिहन्त' की पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **www.arihantbooks.com** पर लॉग इन करें या **info@arihantbooks.com** पर सम्पर्क करें।

Follow us on...

प्रस्तावना

किसी भी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग उद्योग एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि बैंकिंग क्षेत्र का दिन-प्रतिदिन विस्तार किया जा रहा है। फलतः आई बी पी एस (IBPS), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रतिवर्ष पी ओ एवं क्लर्क, (PO-Clerk) अधिकारियों का चयन करने हेतु विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल 'सामान्य सचेतता' खण्ड के अन्तर्गत बैंकिंग जागरूकता को इस आशय के साथ शामिल किया गया है कि अभ्यर्थियों को बैंकिंग कार्य प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान हो। पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि बैंकिंग जागरूकता में अर्थव्यवस्था, बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित स्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निरन्तर बदलती प्रवृत्ति को दृष्टिगत करते हुए की गयी है, इसमें अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय एवं वित्त से सम्बन्धित व्यावहारिक एवं तकनीकी दोनों पक्षों को शामिल किया गया है। पुस्तक में जहाँ अभ्यर्थियों के लिए सारगर्भित प्रमाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, वहीं सतत् अभ्यास करने के लिए समुचित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश भी किया गया है।

इसके साथ ही प्रश्नों की प्रति एवं स्वरूप को समझने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया है, साथ ही पुस्तक में दिए गए 3 प्रैक्टिस सेट्स को हल करने से अभ्यर्थियों को स्वमूल्यांकन करने में विशेष सहायता मिलेगी।

उपरोक्त विशेषताओं से परिपूर्ण यह पुस्तक अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी।

सफलता की कामना के साथ...

लेखक

विषय–सूची

1.	भारतीय बैंकिंग का इतिहास	1-5
2.	भारतीय बैंकिंग संरचना	6-16
3.	भारतीय रिज़र्व बैंक	17-31
4.	बैंकिंग विनिमय प्रणाली	32-39
5.	भारत में बैंकिंग नवाचार	40-50
6.	भारत में बैंकिंग सेवाएँ	51-66
7.	बैंकों में वित्तीय सुधार	67-75
8.	बैंकिंग समिति और बैंकिंग मानक	76-86
9.	भारत के वित्तीय संस्थान	87-95
10.	मुद्रा और वित्तीय बाजार	96-107
11.	पूँजी बाजार	108-121
12.	बीमा और गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ	122-133
13.	भारत में कर प्रणाली	134-141
14.	लोक वित्त और बजट	142-150
15.	भारतीय अर्थव्यवस्था	151-162
16.	उद्योग एवं व्यापार	163-172
17.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और विश्व बैंक	173-186
18.	वित्तीय योजनाएँ	187-199

प्रैक्टिस सेट्स **201-215**
शब्द–संक्षेप **216-221**
शब्दावली **222-233**
वित्तीय और बैंकिंग करेण्ट अफेयर्स **234-267**

अध्याय 01

भारतीय बैंकिंग का इतिहास
(History of Indian Banking)

बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग व अन्य वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराता है। सामान्य तौर पर बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता है, जो ग्राहकों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथ-साथ लोगों की जमा राशि स्वीकार करता है तथा ग्राहकों को ऋण सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

बैंकिंग का अर्थ

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(b) के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से धन जमा करना है। बैंक इन धन के जमाओं को निजी व्यक्तियों और व्यवसायों से स्वीकार्य करती है। इस जमा धन को माँग करने पर लौटाया जा सकता है तथा इसे चेक, ड्राफ्ट आदि द्वारा बैंक से निकाला जा सकता है। बैंकिंग सेवाओं में डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करना, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करना, लॉकर, एटीएम सेवाएँ और धन का ऑनलाइन हस्तान्तरण आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास

भारत में बैंकिंग प्रणाली किसी-न-किसी रूप में प्राचीनकाल से ही मौजूद रही है, लेकिन यह अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक संगठित रूप से विद्यमान नहीं थी।

औपनिवेशिक युग

सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने पर स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली का अन्त होना शुरू हो गया। मैसर्स एलेक्जेण्डर एण्ड कम्पनी ने 1770 ई. में **द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान** के नाम से पहले यूरोपियन बैंक की स्थापना की, जो 1832 ई. में बन्द हो गया।

बंगाल के गवर्नर (बाद में गवर्नर जनरल) वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में केन्द्रीय बैंक की कुछ विशेषताओं के साथ एक बैंकिंग संस्थान की स्थापना की थी। इन्होंने जनवरी, 1773 में **जनरल बैंक ऑफ बंगाल एण्ड बिहार** की स्थापना की थी, लेकिन 1775 ई. में यह बैंक निष्क्रिय हो गया।

भारत में पहला बैंक, **जनरल बैंक ऑफ इण्डिया**, 1786 ई. में स्थापित किया गया था और यह बैंक 1791 ई. में असफल हो गया।

स्वतन्त्रता पूर्व चरण-I (1900)

- देश में निजी अंशधारियों तथा सरकारी अंशधारियों (ईस्ट इण्डिया कम्पनी) द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना की गई। प्रथम प्रेसीडेन्सी बैंक **बैंक ऑफ बंगाल** था, जिसकी स्थापना 2 जून, 1806 को की गई थी।
- द्वितीय तथा तृतीय प्रेसीडेन्सी बैंक की स्थापना **बैंक ऑफ बॉम्बे** (15 अप्रैल, 1840) तथा **बैंक ऑफ मद्रास** (1 जुलाई, 1843) के रूप में हुई। इन बैंकों को सरकारी बैंकों के सभी अधिकार प्राप्त थे, किन्तु 1862 ई. के बाद भारत सरकार ने इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया।
- 1865 ई. में भारतीयों (विशेष रूप से) द्वारा **इलाहाबाद बैंक** की स्थापना हुई।
- सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित 'अवध **कॉमर्शियल बैंक**, भारतीयों द्वारा स्थापित (संचालित) प्रथम बैंक था, जो वर्ष 1958 में असफल हो गया।
- **पंजाब नेशनल बैंक** की स्थापना 1894 ई. में की गई, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। यह पूर्ण रूप से **पहला भारतीय बैंक** था।

स्वतन्त्रता पूर्व चरण-II (1900 के बाद)

- वर्ष 1906 से 1913 के मध्य, **बैंक ऑफ इण्डिया** (1906), **केनरा बैंक** (1906), **इण्डियन बैंक** (1907), **बैंक ऑफ बड़ौदा** (1909), **सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** (1911) और **बैंक ऑफ मैसूर** (1913) की स्थापना की गई।
- वर्ष 1913 से 1917 के बीच बैंकिंग संकट के कारण कई बैंकों को बन्द करना पड़ा। इस कारण से बैंकों के नियमन के लिए केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की गई।
- वर्ष 1921 में सभी (तीन) प्रेसीडेन्सी बैंकों का इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया में विलय कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च मौद्रिक नियामक बैंक **भारतीय रिज़र्व बैंक** की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को की गई। रिज़र्व बैंक का तत्कालीन मुख्यालय कलकत्ता था, जिसे बाद में वर्ष 1937 में मुम्बई स्थानान्तरित कर दिया गया।

स्वतन्त्रता के बाद का चरण

- 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। गोरेवाला कमेटी सिफारिश पर 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इसका नाम बदलकर **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया** रखा गया।
- वर्ष 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर कर दिया गया।
- 19 जुलाई, 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल, 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** की स्थापना नरसिम्हा कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर, 1975 को की गई। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना है।
- शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई, 1982 को **राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक** (NABARD) की स्थापना की गई।
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) की स्थापना 1 जनवरी, 1982 को, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई, 1988 को तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना अप्रैल, 1990 को की गई।
- इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में संरचनागत सुधार करते हुए पेमेण्ट बैंक, लघु वित्त बैंक आदि की स्थापना की गई है, जिसे आगामी अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

बैंकिंग के प्रकार

1. **शाखा बैंकिंग** बैंक का सर्वाधिक प्रचालित रूप है। यह बैंकिंग तन्त्र का अभिन्न अंग भी है। अधिकतर भारतीय आज भी अपने लेन-देन के लिए बैंक की शाखाओं पर निर्भर हैं। इस प्रकार शाखा बैंकिंग (Branch Banking) में ग्राहकों का बैंकिंग कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित होता है। इन शाखाओं में धन जमा करना, निकासी, ऋण सम्बन्धी गतिविधियाँ आदि संचालित होती हैं।
2. **इकाई बैंकिंग** प्रणाली का उद्भव अमेरिका में हुआ था। इकाई बैंकिंग (Unit Banking) के अन्तर्गत बैंक अपनी एक ही इकाई स्थापित करता है। यह प्रणाली बैंकिंग व्यवसाय की सीमित इकाई के रूप में कार्य करती है।
3. **मिश्रित बैंकिंग** जब बैंक वाणिज्यिक बैंक तथा निवेश बैंक की सेवाएँ एक साथ संचालित करता है, तो इस प्रकार की प्रणाली को मिश्रित बैंकिंग (Mixed Banking) कहते है। इस प्रकार की बैंकिंग तेजी से औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
4. **शृंखला बैंकिंग** प्रणाली के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति या संस्थाएँ कुछ बैंकों का स्वामित्व अपने अधीन कर लेती हैं। शृंखला बैंकिंग (Chain Banking) का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समूह द्वारा किया जाता है।
5. **होलसेल बैंकिंग** सामान्यत: होलसेल बैंकिंग (Wholesale Banking) में बड़े निवेशकों, उद्योगपतियों तथा व्यावसायिक बैंकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये बैंकर अपने ग्राहकों के लिए बाज़ार का निर्माण, सलाहकारी सेवाएँ, विलय, अधिग्रहण व संयुक्त उद्यम बनाने जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।
6. **रिलेशनशिप बैंकिंग** प्रणाली साधारण बैंकिंग सेवा से हटकर कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं के लिए कार्य करती है। रिलेशनशिप बैंकिंग (Relationship Banking) के अन्तर्गत ग्राहक की आवश्यकताओं के ऊपर जोर दिया जाता है। यह बैंकिंग क्रॉस सेलिंग सर्विसेज के सिद्धान्त पर कार्य करती है।
7. **कॉरस्पॉण्डेण्ट बैंकिंग** प्रणाली के अन्तर्गत समान एवं असमान वित्तीय संस्थाओं के आधार पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कॉरस्पॉण्डेट बैंकिंग (Correspondent Banking) प्रणाली विदेशों में भी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराती है, जहाँ पर साधारण देशी बैंकिंग संस्थाएँ सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवा सकती हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

8. **यूनिवर्सल बैंकिंग** प्रणाली में बड़े बैंकों के द्वारा बैंकिंग सेवाओं, निवेश बैंक सेवाओं, वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank) सेवाओं व बीमा सेवाओं आदि सभी सेवाओं को एक साथ प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यूनिवर्सल बैंकिंग (Universal Banking) से तात्पर्य ऐसी बैंकिंग प्रणाली से है, जो वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को सभी बैंकिंग गतिविधियों, वित्त आदि से सम्बन्धित कार्य करने की अनुमति देती है।
9. **संकीर्ण बैंकिंग** बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग के विपरीत केवल सीमित सेवाएँ, जैसे फण्ड का ट्रांसफर जैसी गतिविधियाँ ही संचालित करती है, जिसमें न्यूनतम जोखिम हो। इसी कारण तारापोर कमेटी संकीर्ण बैंकिंग (Narrow Banking) गतिविधियों के लिए बल देती है, जिससे कि बैंकों को गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (Non Performing Assets) की समस्या का सामना न करना पड़े।
10. **खुदरा बैंकिंग** प्रणाली में लेनदेन सीधे ग्राहकों के साथ किया जाता हो खुदरा बैंकिंग (Retail Banking) कहलाती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक सभी प्रकार की व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जैसे-बचत खाते, चालू खाते, लेन-देन खाते, गिरवी, ग्राहकों को सीधे व्यक्तिगत ऋण, डेबिट और क्रेडिट कार्ड आदि।
11. **ऑनलाइन बैंकिंग** इस प्रणाली को इण्टरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) कम्प्यूटर या मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके इण्टरनेट से बैंक खाते को प्रबन्धित करने की क्षमता प्रदान करता है। इस बैंकिंग में किसी बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल भुगतान, फण्ड ट्रान्सफर, अकाउण्ट बैलेन्स देखना, बैंक स्टेटमेण्ट आदि इस बैंकिंग के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं।
12. **सामाजिक बैंकिंग** वह प्रणाली जिसके द्वारा गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को उनकी विकास सम्बन्धी जरूरतों के अनुरूप बैंकिंग सेवाएँ, जैसे—ऋण इत्यादि उपलब्ध कराना, न्यूनतम बैलेन्स (Minimum balance) जैसे नियमों में छूट इत्यादि, प्रदान की जाती है, सामाजिक बैंकिंग प्रणाली (Social Banking) कहलाती है।
13. **वर्चुअल बैंकिंग** प्रणाली को प्रत्यक्ष बैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी भी शाखा नेटवर्क के बिना एक बैंक है, जो ऑनलाइन बैंकिंग और टेलीफोन (मोबाइल) बैंकिंग या एक स्वतन्त्र बैंकिंग एजेण्ट नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। यह एटीएम, मेल और मोबाइल के माध्यम से भी अपनी सेवाएँ देता है।

   वर्चुअल बैंकिंग (Virtual Banking), इण्टरनेट बैंकिंग का ही एक स्वरूप है, जिसमें बैंक की शाखा भौतिक रूप में उपस्थित नहीं होती। इसकी सम्पूर्ण गतिविधि कम्प्यूटर के द्वारा ही संचालित होती है।
14. **ग्रामीण बैंकिंग** एक ऐसी व्यवस्था है, जो अपनी सेवा सामान्यत: छोटे ग्रामीण समुदायों को प्रदान करती है। ग्रामीण बैंकिंग (Rural Banking) भारतीय वित्तीय बाजार का अभिन्न अंग बन गई है। अधिकांश भारतीय आबादी अभी भी ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में ही रहती है।

प्रश्न बैंक

1. निम्नलिखित में से किस सेवा को बैंकिंग सेवा के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है?
(a) डेबिट और क्रेडिट कार्ड
(b) लॉकर
(c) एटीएम
(d) धन का ऑनलाइन हस्तान्तरण
(e) ये सभी

2. 1770 ई. में भारत में सर्वप्रथम किस नाम से यूरोपियन बैंक की स्थापना की गई थी?
(a) प्रेसीडेन्सी बैंक (b) इम्पीरियल बैंक
(c) अवध बैंक (d) द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान
(e) जनरल बैंक ऑफ इण्डिया

3. भारत में केन्द्रीय बैंक की कुछ विशेषताओं के साथ एक बैंकिंग संस्थान स्थापित करने का सबसे पहला प्रयास जनवरी, 1773 में बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स (बाद में गवर्नर जनरल) ने किया **[RBI Asst. 2013]**
(a) प्रेसीडेन्सी बैंक
(b) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया
(c) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया
(d) जनरल बैंक ऑफ बंगाल एण्ड बिहार
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

4. निम्नलिखित में से किस वर्ष जनरल बैंक ऑफ इण्डिया स्थापित किया गया?
(a) 1782 ई. (b) 1784 ई.
(c) 1786 ई. (d) 1788 ई.
(e) 1790 ई.

5. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक प्रथम प्रेसीडेन्सी बैंक था?
(a) बैंक ऑफ बंगाल
(b) बैंक ऑफ बॉम्बे
(c) बैंक ऑफ मद्रास
(d) द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान
(e) जनरल बैंक ऑफ इण्डिया

6. सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा स्थापित (संचालित) अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी?
(a) 1881 ई. (b) 1882 ई.
(c) 1883 ई. (d) 1884 ई.
(e) 1885 ई.

7. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक पूर्णरूप से पहला भारतीय बैंक था?
(a) अवध कॉमर्शियल बैंक (b) पंजाब नेशनल बैंक
(c) बैंक ऑफ बॉम्बे (d) बैंक ऑफ कलकत्ता
(e) बैंक ऑफ मद्रास

8. 1894 ई. में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था?
(a) अमृतसर (b) कलकत्ता
(c) बम्बई (d) लाहौर
(e) कराची

9. निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी?
(a) वर्ष 1906 (b) वर्ष 1907
(c) वर्ष 1909 (d) वर्ष 1911
(e) वर्ष 1913

10. वर्ष 1921 में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों का विलय किस बैंक में कर दिया गया?
(a) पंजाब नेशनल बैंक
(b) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया
(c) सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
(d) जनरल बैंक ऑफ इण्डिया
(e) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया

11. भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित किया गया था, ने कार्य करना शुरू किया **[RBI Asst. 2013]**
(a) 1 अप्रैल, 1934 (b) 1 अप्रैल, 1935
(c) 1 सितम्बर, 1934 (d) 1 जुलाई, 1934
(e) 1 अप्रैल, 1936

12. प्रारम्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था?
(a) दिल्ली (b) बम्बई (c) कलकत्ता (d) मद्रास
(e) नागपुर

13. वर्ष 1949 में किस तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? **[IBPS Clerk 2020]**
(a) 1 जनवरी (b) 1 फरवरी
(c) 1 मार्च (d) 1 अप्रैल
(e) 1 मई

14. किस कमेटी की सिफारिश पर 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए, उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रूप में बदल दिया गया?
(a) नरसिम्हा कमेटी (b) केलकर कमेटी
(c) गोरेवाला कमेटी (d) शिवरमन समिति
(e) इनमें से कोई नहीं

15. निम्नलिखित में से किस वर्ष 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
(a) वर्ष 1968 (b) वर्ष 1969
(c) वर्ष 1970 (d) वर्ष 1971
(e) वर्ष 1973

16. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी
(a) 2 अक्टूबर, 1969 (b) 2 अक्टूबर, 1975
(c) 14 नवम्बर, 1989 (d) 14 नवम्बर, 1995
(e) 31 अक्टूबर, 1985

17. निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना अप्रैल, 1990 में हुई थी?
(a) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक
(b) राष्ट्रीय आवास बैंक
(c) ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(d) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
(e) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

18. निम्नलिखित में से किस देश में इकाई बैंकिंग (Unit Banking) का उद्‌भव हुआ?
(a) फ्रांस (b) अमेरिका
(c) इंग्लैण्ड (d) भारत
(e) इनमें से कोई नहीं

19. जब बैंक वाणिज्यिक बैंक तथा निवेश बैंक की सेवाएँ एक साथ संचालित करता है, तो इस प्रकार की प्रणाली कहलाती है
(a) शाखा बैंकिंग (b) इकाई बैंकिंग
(c) मिश्रित बैंकिंग (d) सामाजिक बैंकिंग
(e) इनमें से कोई नहीं

20. मुख्यत: किस प्रकार की बैंकिंग का संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समूह द्वारा किया जाता है?
(a) ऑनलाइन बैंकिंग (b) श्रृंखला बैंकिंग
(c) संकीर्ण बैंकिंग (d) आभासी बैंकिंग
(e) इनमें से कोई नहीं

21. निम्नलिखित में से कौन-सी बैंकिंग क्रॉस सेलिंग सर्विसेज के सिद्धान्त पर कार्य करती है?
(a) रिलेशनशिप बैंकिंग (b) यूनिवर्सल बैंकिंग
(c) होलसेल बैंकिंग (d) संकीर्ण बैंकिंग
(e) खुदरा बैंकिंग

22. ऑनलाइन बैंकिंग के अन्तर्गत किस प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है?
(a) बिल भुगतान (b) फण्ड ट्रान्सफर
(c) बैंक स्टेटमेण्ट (d) यात्रा टिकट का भुगतान
(e) ये सभी

23. बैंकिंग के सन्दर्भ में कौन-सा कथन सही है?
(a) मिश्रित बैंकिंग तेजी से औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है
(b) इकाई बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग व्यवसाय की सीमित इकाई के रूप में कार्य करती है
(c) ऑनलाइन बैंकिंग को इण्टरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है
(d) 'b' तथा 'c'
(e) उपरोक्त सभी

24. कौन-सी बैंकिंग प्रणाली गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को उनकी विकास सम्बन्धी जरूरतों के अनुरूप बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती है?
(a) मिश्रित बैंकिंग (b) होलसेल बैंकिंग
(c) कोरसपॉण्डेण्ट बैंकिंग (d) यूनिवर्सल बैंकिंग
(e) सामाजिक बैंकिंग

25. बिना किसी शाखा नेटवर्क वाला बैंक, जो ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीफोन/मोबाइल बैंकिंग और इण्टरबैंक एटीएम नेटवर्क गठजोड़ के माध्यम से दूरस्थ रूप से अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, के रूप में जाना जाता है **[IBPS Clerk 2013]**
(a) यूनिवर्सल बैंकिंग (b) अप्रत्यक्ष बैंक
(c) डोरस्टेप बैंक (d) प्रत्यक्ष बैंक
(e) इकाई बैंकिंग

उत्तरमाला

1. (e)	**2.** (d)	**3.** (d)	**4.** (c)	**5.** (a)	**6.** (a)	**7.** (b)	**8.** (d)	**9.** (c)	**10.** (b)
11. (b)	**12.** (c)	**13.** (a)	**14.** (c)	**15.** (b)	**16.** (b)	**17.** (e)	**18.** (b)	**19.** (c)	**20.** (b)
21. (a)	**22.** (e)	**23.** (e)	**24.** (e)	**25.** (d)					

अध्याय 02

भारतीय बैंकिंग संरचना
(Indian Banking Structure)

भारतीय बैंकिंग संरचना, संस्थाओं का एक ऐसा समूह है, जो देश में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। भारतीय बैंकिंग उद्योग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र शामिल हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है

1. **संगठित क्षेत्र** इसके अन्तर्गत वे बैंकिंग उद्योग आते हैं, जिनकी गतिविधियाँ नियामक संस्थाओं द्वारा नियमित एवं नियन्त्रित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ शामिल हैं
   - (i) **भारतीय रिज़र्व बैंक** यह भारत में मुद्रा बाजार का सर्वोच्च नियामक है तथा देश का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) भी है।
   - (ii) **वाणिज्यिक बैंक** व्यवसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक (कॉमर्शियल बैंक) उन बैंकों को कहते हैं, जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएँ प्रदान करती है। यह संगठन, व्यवसायों और व्यक्तिगत तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली एक वित्तीय संस्था है। वाणिज्यिक बैंकों का संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक वर्चस्व है। इनके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (SBI और इसके सहयोगी बैंक + राष्ट्रीयकृत बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) एवं निजी क्षेत्र के बैंक (सूचीबद्ध + गैर-सूचीबद्ध + विदेशी बैंक) शामिल हैं।
   - (iii) **सहकारी बैंक** ये बैंक सहकारी साख संस्थाएँ हैं। इनकी संरचना त्रिस्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ शामिल हैं।
2. **असंगठित क्षेत्र** इसकी गतिविधियाँ अनियमित होती हैं। असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) वित्तीय नियामकों द्वारा नियमित व नियन्त्रित भी नहीं होता है। यह मुख्य रूप से देशी बैंकर, चिट-फण्ड निधि आदि से सम्बन्धित है।

केन्द्रीय बैंक

किसी भी देश की सरकार केन्द्रीय बैंकों (Central Banks) के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विशेष उपाय करती है। केन्द्रीय बैंक आमतौर पर मौद्रिक नीति के गठन और सदस्य बैंकों के विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है।

इसके विशिष्ट कार्यों में मौद्रिक नीति को लागू करना, विदेशी मुद्रा और स्वर्ण भण्डार का प्रबन्धन, आधिकारिक ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेना, सरकार और अन्य बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करना भी शामिल हैं। ये बैंक सरकारी ऋण खरीदते हैं।

कागजी मुद्रा जारी करने पर उनका एकाधिकार होता है और अकसर वाणिज्यक बैंकों के लिए अन्तिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं।

केन्द्रीय बैंक किसी भी देश की मुद्रा और ऋण नीतियों को नियन्त्रित और समन्वयित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 1935 को ₹ 5 करोड़ की पूँजी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।

भारतीय बैंकिंग संरचना

भारतीय बैंकिंग संरचना को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
(केन्द्रीय बैंक एवं सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकार)

- अनुसूचित बैंक
  - सार्वजनिक क्षेत्र बैंक
  - निजी क्षेत्र के बैंक
  - भारत में विदेशी बैंक
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  - अनुसूचित सहकारी बैंक
- गैर-अनुसूचित बैंक
  - लोकल एरिया बैंक
  - चिट-फण्ड

1. अनुसूचित बैंक

अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) ऐसे बैंक हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुसूची में 1934 के कानून के अन्तर्गत दर्ज किए गए हैं। इन बैंकों की परिदत्त पूँजी (Paid-up capital) और रिज़र्व पूँजी (Reserve Capital) ₹ 5 लाख से अधिक होती है। इन बैंकों को प्रत्येक सप्ताह भारतीय रिज़र्व बैंक को भी गतिविधियों की जानकारी देनी होती है कि इनका कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप किया जा रहा है। सभी भारतीय व विदेशी वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक **अनुसूचित बैंक** हैं।

2. गैर-अनुसूचित बैंक

ऐसे बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, **गैर अनुसूचित बैंक** (Non-Scheduled Bank) कहलाते हैं। इनकी कुल चुकता पूँजी तथा रक्षित कोष दोनों की धनराशि ₹ 5 लाख से कम होती है।

इन बैंकों को भी सांविधिक नकद कोष शर्तों को मानना पड़ता है, परन्तु ये इस कोष को रिज़र्व बैंक के पास रखने हेतु बाध्य नहीं हैं। प्राय: ये बैंक रिज़र्व बैंक से उधार लेने के अधिकारी नहीं होते, परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक इन्हें उधार दे सकता है।

भारत में अनुसूचित बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

वे सभी बैंक, जिनमें 50% से अधिक शेयर सरकार का हो तथा जिनका पूरा नियन्त्रण आरबीआई करता हो, **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** कहलाते हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) डिफॉल्ट रूप से **वाणिज्यिक बैंक** हैं। वाणिज्य बैंक की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निम्न हैं

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (56.92%)
2. पंजाब नेशनल बैंक (85.59%)
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (71.60%)
4. केनरा बैंक (78.25%)
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (89.07%)
6. इण्डियन बैंक (88.06%)
9. बैंक ऑफ इण्डिया (89.10%)
8. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (92.39%)
9. इण्डियन ओवरसिज बैंक (95.84%)
10. यूको बैंक (94.39%)
11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (92.49%)
12. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक (83.06%)

* सरकारी शेयरधारिता प्रतिशत (%) में (1 जनवरी, 2021 के अनुसार)

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। भारत में बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) करने का निश्चय भारत सरकार द्वारा किया गया। चूँकि, वाणिज्यिक बैंक दूसरी निजी संस्थाओं की तरह स्वलाभ की प्रेरणा से ही व्यवसाय कर रहे थे, जिससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा था व आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा था।

इस प्रक्रिया का दुष्परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र की उपेक्षा होने लगी तथा उन्हें समुचित मात्रा में ऋण प्राप्त नहीं हुआ, जिससे वे विकास की दौड़ में पिछड़ गए।

19 जुलाई, 1969 को उन 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक थी। यह राष्ट्रीयकृत बैंक निम्न है

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
2. पंजाब नेशनल बैंक
3. बैंक ऑफ इण्डिया
4. केनरा बैंक
5. इलाहाबाद बैंक
6. बैंक ऑफ बड़ौदा
7. सिण्डीकेट बैंक
8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
9. यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
10. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
11. इण्डियन बैंक
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
13. देना बैंक
14. इण्डियन ओवरसीज बैंक

15 अप्रैल, 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी जमा राशि ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक थी, जो इस प्रकार हैं

1. आन्ध्रा बैंक
2. कॉर्पोरेशन बैंक
3. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
4. न्यू बैंक ऑफ इण्डिया
5. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
6. विजया बैंक

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

4 सितम्बर, 1993 को न्यू बैंक ऑफ इण्डिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों का **प्रथम विलय** था।

एसबीआई के साथ सहयोगी बैंकों का विलय

- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित किया।
- इम्पीरियल बैंक का निर्माण वर्ष 1921 में प्रेसीडेन्सी बैंक अर्थात् बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुम्बई और बैंक ऑफ मद्रास के विलय से हुआ था।
- भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल, 2017 को अपने में विलय कर लिया। इस तरह से एसबीआई बैंक विश्व के प्रमुख 50 बैंकों में शामिल हो गया।
- 5 सहयोगी बैंक जिनका एसबीआई में विलय किया गया।
  — स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (स्थापना वर्ष 1913)
  — स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (स्थापना वर्ष 1917)
  — स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (स्थापना वर्ष 1941)
  — स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर (स्थापना वर्ष 1943)
  — स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (स्थापना वर्ष 1945)

भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 19 नवम्बर, 2013 को निगमित किया गया। महिला बैंक को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया। यह पहला बैंक था, जो संसद के अधिनियम से निगमित किया गया था।

इस बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने किया था, जिसका मुख्यालय मुम्बई में था। वर्ष 2021 से यह बैंक एसबीआई का सहयोगी बैंक हो गया।

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

- 1 अप्रैल, 2020 को ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक देश का **दूसरा सबसे बड़ा बैंक** बना गया।
- 1 अप्रैल, 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक का विलय किया गया। इसके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा **देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक** बन गया।
- केनरा बैंक में सिण्डिकेट बैंक के विलय के साथ 1 अप्रैल, 2020 को केनरा बैंक **चौथा सबसे बड़ा बैंक** हो गया।
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को भारत का **पाँचवाँ सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बैंक** 1 अप्रैल, 2020 बनाया गया।
- इण्डियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलयन 1 अप्रैल, 2020 को किया गया। इस प्रकार वर्तमान में (जून, 2021 के अनुसार), भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंक) की कुल संख्या, जो 2017 में 27 थी, से घटकर 12 हो गई है।

निजी बैंक

निजी कम्पनियों द्वारा स्थापित बैंक **निजी बैंक** (Private Bank) कहलाते हैं। इसके लिए लाइसेन्स भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया जाता है।

निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देश

- केवल भारतीय ही निजी क्षेत्र के बैंक खोल सकते हैं।
- इसके लिए न्यूनतम चुकता पूँजी ₹ 500 करोड़ होनी चाहिए।

- हॉल्डिंग कम्पनियों को नए बैंकों को 2 वर्ष के अन्दर शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होगा।
- नए बैंकों पर कम-से-कम 25% शाखाएँ बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से पिछले क्षेत्रों में खोलने की शर्त लगाने का भी प्रस्ताव नए दिशा-निर्देश में है।
- सार्वजनिक क्षेत्र निजी बैंक नहीं खोल सकते।

निजी बैंक के प्रकार

1. **पुराने निजी बैंक** वर्ष 1969 में जो बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं हुए थे, उन्हें निजी बैंक माना गया। इन्हीं बैंकों को ही पुराने निजी बैंक (Old Private Sector Bank) कहते हैं। इन बैंकों के राष्ट्रीयकृत न होने का प्रमुख कारण इनकी छोटी संरचना तथा क्षेत्र विशेष में कार्यरत होना था।
2. **नए निजी बैंक** उन बैंकों को जो वर्ष 1991 के बाद निजी क्षेत्र में शुरू किए गए, नए निजी बैंक (New Private Sector Bank) कहते हैं। वर्ष 1993 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में नए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को अनुमति दी।

   वर्ष 2008 में एचडीएफसी बैंक द्वारा सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का अधिग्रहण किया गया था। वर्ष 2015 में कोटक महिन्द्रा का आइएनजी व्यास बैंक में विलय हो गया। बन्धन बैंक फाइनेन्स को वर्ष 2015 में आरबीआई द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेन्स प्रदान किया गया था। इस बैंक की पंचलाइन 'अपना भला, सबकी भलाई' है। वर्तमान में (जून, 2021 के अनुसार) *भारत में कुल 21 नए निजी बैंक हैं।*

भारत में कुल निजी बैकों की सूची

बैंक का नाम	स्थापना	मुख्यालय
सिटी यूनियन बैंक	1904	तंजावुर (तमिलनाडु)
करूर वैश्य बैंक	1916	करूर (तमिलनाडु)
सीएसबी बैंक	1920	त्रिशूर (केरल)
तमिलनाडु मर्सेनटाइल बैंक	1921	तूतुकुड़ी (तमिलनाडु)
नैनीताल बैंक	1922	नैनीताल (उत्तराखण्ड)
कर्नाटका बैंक	1924	मंगलौर (कर्नाटक)
धनलक्ष्मी बैंक	1927	त्रिशूर (केरल)
साउथ इण्डियन बैंक	1929	त्रिशूर (केरल)
डीसीबी बैंक	1930	मुम्बई (महाराष्ट्र)
फेडरल बैंक	1931	कोच्चि (केरल)
जम्मू और कश्मीर बैंक	1938	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
आरबीएल बैंक	1943	मुम्बई (महाराष्ट्र)
आईडीबीआई बैंक	1964	मुम्बई (महाराष्ट्र)
एक्सिस बैंक	1993	मुम्बई (महाराष्ट्र)
एचडीएफसी बैंक	1994	मुम्बई (महाराष्ट्र)
आईसीआईसीआई बैंक	1994	मुम्बई (महाराष्ट्र)
इन्डसइण्ड बैंक	1994	मुम्बई (महाराष्ट्र)
कोटक महिन्द्रा बैंक	2003	मुम्बई (महाराष्ट्र)
यस बैंक	2004	मुम्बई (महाराष्ट्र)
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	2015	मुम्बई (महाराष्ट्र)
बन्धन बैंक	2015	कोलकाता (प. बंगाल)

विदेशी बैंक

विदेशी बैंक (Foreign Bank) वह है, जिसका मुख्यालय किसी अन्य देश में है, लेकिन भारत में एक निजी बैंक के रूप में कार्य करता है। ये बैंक अपने देश के साथ-साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित सभी बैंकिंग नियम और कानूनों का भी पालन करने के लिए बाध्य हैं।

भारत में कार्य करने वाले कुछ प्रमुख विदेशी बैंक-स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक (96), एचएसबीसी लि. (50), सिटी बैंक (42) और रॉयल बैंक स्कॉटलैण्ड (31) आदि हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks) की स्थापना **नरसिंहम समिति** (1975) की सिफारिशों के आधार पर 26 सितम्बर, 1975 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 से प्रारम्भ हुई थी। तब 5 क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक है, जिसका मुख्यालय मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित है। इसकी प्रारम्भिक पूँजी ₹ 5 करोड़ थी। इस बैंक को सिण्डिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय अनुसूची वाणिज्यिक बैंक है। इसका मुख्य कार्य छोटे और सीमान्त किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों; कारीगरों को बैंकिंग सुविधाएँ और ऋण उपलब्ध कराना साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है।

12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड की स्थापना के बाद आरआरबी का नियन्त्रण नाबार्ड को सौंप दिया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के माध्यम से इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 2 अक्टूबर, 1975 से इन बैंकों ने अपना कार्य करना प्रारम्भ किया।

प्रारम्भ में निम्न 5 क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए

1. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
3. भिवानी (हरियाणा)
4. जयपुर (राजस्थान)
5. माल्दा (पश्चिम बंगाल)

गोवा, चण्डीगढ़, अण्डमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव राज्य/केन्द्रशासित राज्यों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। वर्तमान में देश में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं (जून, 2021 के अनुसार)।

प्रत्येक आरआरबी की अधिकृत पूँजी ₹ 1 करोड़ और जारी व चुकता पूँजी ₹ 25 लाख थी। आरआरबी की हिस्सा पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा लीड बैंक द्वारा 35% का योगदान दिया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन अधिनियम, 2015

- इस संशोधन के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण अधिनियम, 1976 को संशोधित किया गया।
- इसके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना में सुधार कर पूँजी के आधार को बढ़ाया गया।
- इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूँजी को ₹ 5 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2 हजार करोड़ कर दिया गया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अन्य स्रोतों से भी पूँजी जुटाने की अनुमति प्रदान की गई तथा ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार एवं प्रयोजक बैंक की अंशधारिता 51% तक निर्धारित की गई।
- अधिनियम के अनुसार यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सम्बन्धित राज्य की अंशधारिता 15% से कम हो जाती है, तो केन्द्र सरकार उस राज्य सरकार से परामर्श करेगी।

सहकारी बैंक

सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks) को पंजीकृत किया जाता है एवं इन्हें बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 और बैंकिंग विधि अधिनियम, 1955 द्वारा प्रशासित किया जाता है। भारत में सहकारी बैंक का संगठन त्रिस्तरीय है।

सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा होती है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं।

ये सामान्यत: छोटे किसानों, कर्मचारियों और लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। सहकारी बैंक का त्रिस्तरीय संचरना इस प्रकार है

1. **राज्य सहकारी बैंक** इस बैंक को राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक भी कहते हैं। यह भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है यह जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है तथा उसके कार्यों को नियमित करता है। इसे नाबार्ड एवं राज्य सरकार द्वारा पूँजी प्रदान की जाती है। यह रिज़र्व बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है।
2. **जिला सहकारी अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक** इसका कार्यक्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है। इसके खाताधारकों में प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा आम आदमी भी सम्मिलित होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें विशुद्ध बैंक (इसके सदस्य केवल प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ ही होती हैं) और मिश्रित बैंक (इसमें व्यक्ति और समितियाँ दोनों वर्गों के सदस्य होते हैं) होते हैं।
3. **प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ** इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता ही पूर्ति के लिए की गई है। इसका निर्माण एक गाँव अथवा क्षेत्र के कम-से-कम 10 व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं।

भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक

1. **बैंक ऑफ बड़ौदा** (Bank of Baroda, BOB)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE)
स्थापना 20 जुलाई, 1908
मुख्यालय वड़ोदरा (बड़ौदा), गुजरात
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'India's International Bank'

2. **बैंक ऑफ इण्डिया** (Bank of India)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE और BOI)
स्थापना 7 सितम्बर, 1906
मुख्यालय मुम्बई, महाराष्ट्र (भारत)
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Relationships Beyond Banking'

3. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** (Bank of Maharashtra)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE और NSE)
स्थापना 16 सितम्बर, 1935
मुख्यालय शिवाजीनगर, पुणे
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'One Family One Bank'

4. **केनरा बैंक** (Canara Bank)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी
स्थापना 1906
मुख्यालय बंगलुरू, कर्नाटक (भारत)
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'It's easy to Change for those who you love, Together we can'

5. **सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** (Central Bank of India)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE और NSE)
स्थापना 21 दिसम्बर, 1911
मुख्यालय मुम्बई, भारत
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Build A Better Lift Around Us'

6. **इण्डियन बैंक** (Indian Bank)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE और NSE)
स्थापना 5 मार्च, 1907
मुख्यालय चेन्नई, भारत
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Taking Banking Technology to Common man, your tech-friendly bank'

7. **इण्डियन ओवरसिज बैंक** (IOB)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE)
स्थापना 10 फरवरी, 1937
मुख्यालय चेन्नई, भारत
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Good People to Growth with'

8. **पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक** (Punjab & Sind Bank)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी
स्थापना 24 जून, 1908
मुख्यालय राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली
राष्ट्रीयकरण 1980
पंचलाइन 'Where Service is a Way of Life'

9. **पंजाब नेशनल बैंक** (Punjab National Bank)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE और NSE)
स्थापना 1895
मुख्यालय नई दिल्ली, भारत
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'The Name you can Bank upon'

10. **भारतीय स्टेट बैंक** (SBI)

बैंक का प्रकार बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ
स्थापना 1 जुलाई, 1955
मुख्यालय मुम्बई
पंचलाइन Pure Banking Nothing Else

11. **यूको बैंक** (UCO Bank)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक बैंक (NSE और BSE)
स्थापना 6 जनवरी, 1943
मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Honors your Trust'

12. **यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** (Union Bank of India)

बैंक के प्रकार सार्वजनिक कम्पनी (BSE)
स्थापना 11 नवम्बर, 1919
मुख्यालय मुम्बई, भारत
राष्ट्रीयकरण 1969
पंचलाइन 'Good People to Bank With'

प्रश्न बैंक

1. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का संगठित क्षेत्र का बैंक नहीं है? **[IBPS 2020]**
(a) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया
(b) भारतीय स्टेट बैंक
(c) निधि
(d) पंजाब नेशनल बैंक
(e) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2. निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक बैंक के अन्तर्गत नहीं माना जाता है? **[SBI PO 2017]**
(a) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(b) निजी क्षेत्र के बैंक
(c) विकास बैंक
(d) विदेशी बैंक
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

3. निम्नलिखित में कौन-सा बैंक संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है?
(a) राष्ट्रीयकृत बैंक (b) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(c) सहकारी बैंक (d) चिट और फण्ड
(e) औद्योगिक बैंक

4. निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अन्तर्गत आता है?
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(b) निजी क्षेत्र के बैंक
(c) भारत में विदेशी बैंक
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. बैंकों का बैंक किसे कहा गया है?
(a) PSC (b) RBI (c) RRB (d) PNB
(e) ये सभी

6. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? **[RBI Assist 2013]**
(a) केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीय जनकल्याण के लिए कार्य करते हैं
(b) केन्द्रीय बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं
(c) केन्द्रीय बैंक नई तकनीकों से प्रभावित होते हैं
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

7. वाणिज्यिक बैंक किसके अन्तर्गत आते हैं?
(a) बैंकिंग नियामक की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत
(b) संविधान की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत
(c) RBI एक्ट की दूसरी अनुसूची के अन्तर्गत
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
(e) उपरोक्त सभी

8. भारतीय रिज़र्व बैंक एक्ट, 1934 की धारा-42 (6)(a) किससे सम्बन्धित है?
(a) संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र
(b) केवल अंसगठित क्षेत्र
(c) अनुसूचित बैंक
(d) गैर-अनुसूचित बैंक
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. अनुसूचित बैंक किस आधार पर रिज़र्व बैंक और इण्डिया को अपनी कार्य रिपोर्ट सौंपता है?
(a) मासिक आधार पर
(b) वार्षिक आधार पर
(c) दैनिक आधार पर
(d) साप्ताहिक आधार पर
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. भारत में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया
(a) 19 जुलाई, 1969
(b) 19 जून, 1970
(c) 19 जून, 1967
(d) 15 जुलाई, 1967
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. भारत में प्रथम बार में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था?
(a) 10 (b) 20 (c) 14 (d) 16
(e) 24

12. 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों की पूँजी का आधार कितना था? **[IBPS PO 2015]**
(a) 1000 करोड़ (b) 500 करोड़
(c) 100 करोड़ (d) 50 करोड़
(e) इनमें से कोई नहीं

13. बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने का प्रमुख उद्देश्य नहीं था
(a) कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात के लिए धन उपलब्ध कराना
(b) पूँजीपतियों के नियन्त्रण को खत्म करने के लिए
(c) केवल बड़े औद्योगिक इकाइयों को धन का आवण्टन
(d) बैंकों की पहुँच को व्यापक स्तर तक पहुँचाना
(e) उद्यमिता के वर्ग को प्रोत्साहित करना

14. भारत में बैंकों को दूसरी बार वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया था, इसके अन्तर्गत इनमें से किस बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था?
(a) इण्डियन ओवरसीज बैंक
(b) सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
(c) केनरा बैंक
(d) विजया बैंक
(e) देना बैंक

15. भारत में दूसरे चरण के अन्तर्गत कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया?
(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7
(e) 9

16. भारत में बैंकों का दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
(a) 9 जुलाई, 1969 (b) 10 जुलाई, 1968
(c) 16 अगस्त, 1985 (d) 15 अगस्त, 1980
(e) इनमें से कोई नहीं

17. वर्ष 1980 में जिन बैकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, उनमें से कितने बैंक वर्तमान में क्रियाशील हैं?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8
(e) 9

18. निम्नलिखित में कौन-सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं थे? **[SBI Clerk 2012]**
(a) सहकारी बैंक
(b) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
(c) विजया बैंक
(d) बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(e) फेडरल बैंक

19. राष्ट्रीयकृत बैंक का सर्वप्रथम विलय किस वर्ष हुआ था?
(a) वर्ष 1993 (b) वर्ष 1999
(c) वर्ष 2000 (d) वर्ष 2017
(e) वर्ष 2019

20. इम्पीरियल बैंक को परिवर्तित किया गया
(a) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया में
(b) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में
(c) सहायक बैंकों में
(d) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में
(e) कोर्पोरेशन बैंक में

21. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वर्ष 1980 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित है?
(a) इसके अन्तर्गत 200 करोड़ की पूँजी वाले 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था
(b) इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने बैंक क्षेत्र के 91% क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था
(c) इस समय राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों ने कृषि क्षेत्र पर प्रमुख ध्यान दिया
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

22. किसके द्वारा महिला बैंक का उद्घाटन किया गया। **[SBI Clark 2014]**
(a) सोनिया गाँधी (b) पी चिदम्बरम
(c) मनमोहन सिंह (d) डी सुब्बाराव
(e) इनमें से कोई नहीं

23. विजया बैंक और देना बैंक को किसके साथ समायोजित किया गया? **[SBI PO 2020]**
(a) पंजाब नेशनल बैंक
(b) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
(c) ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(d) बैंक ऑफ बड़ौदा
(e) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

24. निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है? **[IBPS Clerk 2019]**
(a) सिण्डीकेट बैंक
(b) कॉर्पोरेशन बैंक
(c) इलाहाबाद बैंक
(d) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

25. बैंक ऑफ बड़ौदा में किस वर्ष दो बैंकों को समायोजित किया गया था?
(a) वर्ष 2016 (b) वर्ष 2017
(c) वर्ष 2018 (d) वर्ष 2019
(e) वर्ष 2020

26. भारत सरकार ने इलाहाबाद बैंक का समायोजन किस बैंक के साथ किया है?
(a) इण्डियन बैंक
(b) देना बैंक
(c) केनरा बैंक
(d) पंजाब नेशनल बैंक
(e) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

27. वर्तमान (2021) में, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है?
(a) 8 (b) 20
(c) 28 (d) 12
(e) इनमें से कोई नहीं

28. कोटक महिन्द्रा बैंक का संयोजन ······ में वर्ष 2014 में हुआ था?
(a) आईएनजी वैश्य बैंक
(b) आईडीबीआई लिमिटेड
(c) बैंक ऑफ राजस्थान
(d) बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड
(e) एक्सिस बैंक

29. निम्नलिखित में से किस बैंक ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का अधिग्रहण किया?
(a) आईसीआईसीआई बैंक
(b) आईडीबीआई बैंक
(c) एचडीएफसी बैंक
(d) एक्सिस बैंक
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

30. निम्नलिखित में से कौन-सा निजी बैंक नहीं है?
(a) एक्सिस बैंक
(b) आईसीआईसीआई बैंक
(c) यूको बैंक
(d) एचडीएफसी बैंक
(e) साउथ इण्डियन बैंक लिमिटेड

31. IDBI बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? **[IBPS Clerk 2015, SBI Clerk 2016]**
(a) हैदराबाद (b) चेन्नई
(c) बंगलुरू (d) कोलकाता
(e) मुम्बई

32. वर्ष 2015 में किन निजी बैंकों का समायोजन हुआ है? **[IBPS Clerk 2015]**
(a) यूनाटेड वेस्टन बैंक और आईडीबीआई बैंक
(b) गणेश बैंक ऑफ कुरुधवाड और फेडरल बैंक
(c) आईएनजी वैश्य बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक
(d) बैंक ऑफ राजस्थान और आईसीआईसीआई बैंक
(e) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

33. आईडीएफसी बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
(a) वर्ष 1935 (b) वर्ष 1969
(c) वर्ष 1975 (d) वर्ष 1995
(e) वर्ष 2004

34. बन्धन बैंक की टैग लाइन है **[IBPS PO 2015 Main]**
(a) अपना भला आपकी भलाई
(b) आपका भला सबकी भलाई
(c) ख्याल आपका
(d) बैंकिंग दा अनबैकण्ड
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

35. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्गीकरण किसके अन्तर्गत किया गया है?
(a) भूमि सुधार बैंक (b) सहकारी बैंक
(c) वाणिज्यिक बैंक (d) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
(e) इनमें से कोई नहीं

36. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके स्वामित्व में होते हैं?
(a) केन्द्र सरकार (b) राज्य सरकार
(c) प्रायोजित बैंक (d) ये सभी
(e) इनमें से कोई नहीं

37. निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? **[SBI Clerk 2014]**
(a) कर्नाटक (b) गोवा
(c) उत्तराखण्ड (d) हिमाचल प्रदेश
(e) पंजाब

38. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम के अन्तर्गत बैंकिंग सम्बन्धी कार्य करता है? **[IBPS Clerk 2015]**
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976
(b) बैंकिंग रेग्यूलेशन बैंक अधिनियम, 1976
(c) रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम
(d) कम्पनीज अधिनियम, 1956
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

39. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में किसकी हिस्सेदारी होती है?**
(a) केवल केन्द्र सरकार की
(b) केवल राज्य सरकार की
(c) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजित बैंक की हिस्सेदारी (क्रमश: 50 : 15 : 35 प्रतिशत) होती है
(d) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी (50 : 50 प्रतिशत) होती है
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. **केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रत्यक्ष रूप से किसके सम्पर्क में रहता है?**
(a) किसान
(b) राज्य सहकारी बैंक
(c) भूमि सुधार बैंक
(d) केन्द्र सरकार
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

41. **ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंक को किस नाम से जाना जाता है?**
(a) केन्द्रीय सहकारी बैंक
(b) प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी
(c) ग्रामीण सहकारी बैंक
(d) राज्य सहकारी बैंक
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

42. **सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?** **[IBPS PO Main 2015]**
(a) नई दिल्ली (b) मुम्बई
(c) पुणे (d) बंगलुरू
(e) इनमें से कोई नहीं

43. **पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनी है। इसका मुख्यालय है** **[RBI Assit. 2015]**
(a) नई दिल्ली (b) मुम्बई
(c) चण्डीगढ़ (d) जयपुर
(e) इनमें से कोई नहीं

44. **यूनियन बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, इसका मुख्यालय है** **[RBI Grade B 2015]**
(a) मुम्बई (b) बंगलुरू
(c) नई दिल्ली (d) चेन्नई
(e) कोलकाता

45. **वर्तमान में स्थित इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कौन-से मात्र एक बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 है?**
(a) केनरा बैंक
(b) बैंक ऑफ बड़ौदा
(c) इण्डियन ओरसीज बैंक
(d) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
(e) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

उत्तरमाला

1. (c)	**2.** (c)	**3.** (d)	**4.** (d)	**5.** (b)	**6.** (b)	**7.** (c)	**8.** (c)	**9.** (d)	**10.** (a)
11. (c)	**12.** (d)	**13.** (c)	**14.** (c)	**15.** (c)	**16.** (d)	**17.** (b)	**18.** (e)	**19.** (a)	**20.** (b)
21. (a)	**22.** (c)	**23.** (d)	**24.** (d)	**25.** (d)	**26.** (a)	**27.** (d)	**28.** (a)	**29.** (c)	**30.** (c)
31. (e)	**32.** (c)	**33.** (d)	**34.** (b)	**35.** (d)	**36.** (d)	**37.** (b)	**38.** (a)	**39.** (c)	**40.** (b)
41. (b)	**42.** (b)	**43.** (a)	**44.** (a)	**45.** (e)					

अध्याय 03

भारतीय रिज़र्व बैंक
(Reserve Bank of India)

भारतीय रिज़र्व बैंक हमारे देश का केन्द्रीय बैंक (Central Bank) है। इसका मुख्यालय मुम्बई (महाराष्ट्र) में है। भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank) भारतीय मुद्रा की छपाई और आपूर्ति के साथ-साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए भी उत्तरदायी है। भारतीय रिज़र्व बैंक देश का सर्वोच्च मौद्रिक एवं बैंकिंग प्राधिकरण (Monetary and Banking Authority) है। देश में बैंकिंग प्रणाली को नियन्त्रित करने का दायित्व इसी बैंक पर है।

रिज़र्व बैंक का इतिहास

वर्ष 1927 में सर्वप्रथम रिज़र्व बैंक के गठन का प्रस्ताव जॉन हिल्टन यंग कमीशन द्वारा रखा गया, जिसे **रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेन्सी एण्ड फिनान्स** के नाम से भी जाना जाता है।

वर्ष 1933 में जॉर्ज शूस्टर द्वारा निर्मित बिल को विधानसभा द्वारा मंजूरी दी गई। वर्ष 1934 में जॉर्ज शूस्टर के बिल को भारतीय **रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934** के नाम से कानूनी रूप दिया गया। 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अन्तर्गत **भारतीय रिज़र्व बैंक** (Reserve Bank of India, RBI) की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया।

जनवरी, 1949 के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिनियम 1948 के तहत आरबीआई सार्वजनिक स्वामित्व से बदलकर राज्य (केन्द्र सरकार) के स्वामित्व वाला बैंक बन गया। अब आरबीआई का स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 ने आरबीआई को गहन शक्ति प्रदान की।

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन एवं प्रबन्धन

- रिज़र्व बैंक में सामान्य प्रबन्ध एवं निर्देशन का कार्य 21 सदस्यों (जून, 2021 के अनुसार) पर आधारित केन्द्रीय निदेशक मण्डल को सौंपा गया है।
- इसमें एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, एक वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित दस ऐसे निर्देशक होते हैं, जो देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और चार निदेशक स्थानीय बोर्डों (Local Boards) का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए नामित किए जाते हैं।
- केन्द्रीय बोर्ड मुम्बई में स्थापित है। इसके अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड भी हैं, जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई (मुम्बई), कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) और नई दिल्ली में हैं। जहाँ पर भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्यालय नहीं है, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के कुल **31 क्षेत्रीय कार्यालय** (4 उप-कार्यालय के साथ) हैं, जो मुख्यत: राज्य की राजधानी में हैं।
- स्थानीय बोर्डों के पाँच सदस्य होते हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनमें क्षेत्रीय एवं आर्थिक हितों और सरकारी एवं देशी बैंकों को प्रतिनिधित्व मिलता है।
- वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी प्राय: भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो सरकार की इच्छानुसार बोर्ड (मण्डल) में बना रहता है।

- आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। यह परिवर्तन वित्त वर्ष 2020-21 से किया गया है। इससे पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था। आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अगस्त में जारी करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रथम गवर्नर **सर आसबोर्न स्मिथ** थे, जबकि **सी डी देशमुख** पहले भारतीय गवर्नर थे। ₹ 1 को छोड़कर शेष सभी भारतीय मुद्रा के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। गवर्नर का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष के लिए होता है और कुछ मामलों में इस कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर एवं उनका कार्यकाल

गवर्नर	कार्यकाल
सर आसबोर्न स्मिथ	1 अप्रैल 1935 से 30 जून, 1937
सर जेम्स टेलर	1 जून 1937 से 17 फरवरी 1943
सर सी डी देशमुख	11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949
सर बेनेगल रामाराव	1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957
के जी अम्बेगावकर	14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957
एच वी आर आयंगर	1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962
पी सी भट्टाचार्य	1 मार्च 1962 से 30 जून 1967
एल के झा	1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970
बी एन अदारकर	4 मई 1970 से 15 जून 1970
एस जगन्नाथन	16 जून 1970 से 19 मई 1975
एन सी सेनगुप्ता	19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975
के आर पुरी	20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977
एम नरसिंहम	2 मई 1977 से 30 नवम्बर 1977
आई जी पटेल	1 दिसम्बर 1977 से 15 सितम्बर 1982
डॉ. मनमोहन सिंह	16 सितम्बर 1982 से 14 जनवरी 1985
ए घोष	15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985
आर एन मल्होत्रा	4 फरवरी 1985 से 22 दिसम्बर 1990
एस वेंकटरमन	22 दिसम्बर 1990 से 21 दिसम्बर 1992
डॉ. सी रंगराजन	22 दिसम्बर 1992 से 21 नवम्बर1997
डॉ. विमल जालान	22 नवम्बर 1997 से 6 सितम्बर 2003
डॉ. वाई वी रेड्डी	6 सितम्बर 2003 से 5 सितम्बर 2008
डी. सुब्बाराव	5 सितम्बर 2008 से 4 सितम्बर 2013
रघुराम गोविन्द राजन	4 सितम्बर 2013 से 5 सितम्बर 2016
उर्जित पटेल	6 सितम्बर 2016 से 11 दिसम्बर 2018
शक्तिकान्त दास	12 दिसम्बर 2018 से अब तक

(* 30 सितम्बर, 2021 के अनुसार)

RBI केन्द्रीय बोर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। रिज़र्व बैंक का कारोबार केन्द्रीय बोर्ड के निर्देशक करते हैं। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। केन्द्रीय बोर्ड की प्रमुख सहायक संस्थाएँ निरीक्षण, ऑडिट और स्टाफ सम्बन्धी गतिविधियाँ सम्पन्न करती हैं।

तीन बोर्ड/समितियों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाती है, ये समितियाँ निम्नलिखित हैं

1. **केन्द्रीय बोर्ड की समिति** (Committee of Central Board, CCB) यह आरबीआई की सबसे महत्त्वपूर्ण समिति है। यह बैंकिंग क्षेत्रों और मौद्रिक नीतियों के विनियमन के मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए प्रत्येक बुधवार को बैठक करता है।
2. **वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड** (Board for Financial Supervision, BFS) रिज़र्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार करता है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (NBFCs) सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है।
3. **भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण सम्बन्धी बोर्ड** (Board for Payment and Settlement System, BPSS) भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी केन्द्रीय बैंक का कार्य है, जिसके द्वारा मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और दक्षता (पूर्णता) के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके द्वारा आरबीआई जनता का विश्वास बनाए रखता है।

अन्य सहायक संस्थान

- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्रा. लिमिटेड (ReBIT) (पूर्ण स्वामित्व वाला)।
- भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारण्टी निगम (DICGC)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)।
- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध सेवाएँ (IFTAS) शामिल हैं, इसके अतिरिक्त नाबार्ड में भी RBI की बड़ी हिस्सेदारी है।

अनुसन्धान संस्थान

भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न बैंकिंग नियमन गतिविधियों पर सलाह देने के लिए अनेक अनुसन्धान संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान बैंकिंग मामलों के अतिरिक्त भी आर्थिक विकास एवं तकनीकी विकास पर भी भारतीय रिज़र्व बैंक को सहायता प्रदान करते हैं। ये तीन संस्थान हैं

1. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM) पुणे।
2. इन्दिरा गाँधी विकास अनुसन्धान संस्थान (IGIDR) मुम्बई।
3. बैंकिंग तकनीक विकास एवं अनुसन्धान संस्थान (IDRBT) हैदराबाद।

आरबीआई का प्रशिक्षण संस्थान

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए तीन संस्थान है। इनमें आरबीआई अकादमी, कृषि बैंकिंग कॉलेज और आरबीआई स्टाफ कॉलेज शामिल हैं

(i) आरबीआई अकादमी की स्थापना 2016 में प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हुई।

(ii) कृषि बैंकिंग कॉलेज की स्थापना 29 सितम्बर, 1969 को पुणे में सहकारी बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेज के नाम से हुई थी। बाद में वर्ष 1974 में इसका नाम बदलकर कृषि बैंकिंग कॉलेज कर दिया गया।

(iii) रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज की स्थापना 3 जुलाई, 1963 को चेन्नई में हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य

- **मौद्रिक प्राधिकारी** यह मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन करता है और उसकी निगरानी भी करता है। इसका उद्‌देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और उत्पादक क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
- **नोटों का निर्गमन** रिज़र्व बैंक को देश की एकमात्र नोट जारी करने वाली एजेन्सी कहा जाता है। रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 1 का नोट जारी नहीं किया जाता। यह नोट कार्य वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किया जाता है। रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 2, ₹ 5, ₹ 10, ₹ 20, ₹ 50, ₹100, ₹ 200, ₹ 500, ₹ 2000 के नोट जारी किए जाते हैं। नोट जारी करने के लिए बैंक के पास एक अलग विभाग है। इसे अंक विभाग के रूप में जाना जाता है।
- **सरकार का बैंकर** रिज़र्व बैंक सरकार का बैंकर (Banker of the Government) एवं परामर्शदाता है। साथ ही यह केन्द्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों का बैंकिंग प्रतिनिधि है। यह भारत सरकार का बैंक व्यापार करता है अर्थात् भारत सरकार के लिए रुपया स्वीकार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार के रुपयों की अदायगी, प्रेषण (Remittance) एवं अन्य बैंकिंग क्रियाएँ (Banking Operations) भी करता है।
- **बैंकों का बैंकर एवं अन्तिम ऋणदाता** रिज़र्व बैंक को बैंकों के बैंकर का कार्य करना पड़ता है। बैंकों को अपनी समग्र जमा देयता (Aggregate Deposit Liabilities) का 3% रिज़र्व बैंक के पास नकद प्रारक्षण (Cash Reserve) में रखना होता है। रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार न्यूनतम नकद प्रारक्षण की मात्रा बदली जा सकती है। आवश्यकता के समय या विपत्ति काल में अनुसूचित बैंक आरबीआई से अपने विनिमय-पत्रों का बट्‌टा करवाकर वित्तीय निभाव (Financial Accommodation) प्राप्त कर सकते हैं।
- **वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक** आरबीआई देश में समग्र वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखता है। आरबीआई ब्याज दरों को नियमित करता है और जनता को सकारात्मक बैंकिंग विकल्प प्रदान करता है।

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से अभिप्राय केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में लिखतों के उपयोग से है, जिससे कि मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियन्त्रित किया जा सके।

इसका उद्‌देश्य कम और स्थिर मुद्रास्फीति तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों को अर्जित करना है। यह उच्च विकास दर के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है तथा मूल्य स्थिरता बनाए रखता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। यह जिम्मेदारी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।

मौद्रिक नीति का लक्ष्य

- मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता संधारणीय वृद्धि की आवश्यक शर्त है।
- मई 2016 में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया, जिससे कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए सांविधिक आधार प्रदान किए जा सके।
- आरबीआई अधिनियम में आरबीआई के साथ मिलकर भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है।

मौद्रिक नीति समिति

- आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee, MPC) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अन्तर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- एमपीसी की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती हैं।
- केन्द्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन और केन्द्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की स्थापना को अधिसूचित किया है।
- RBI एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होंगे और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की सलाह पर आरबीआई करेगा।
- मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आरबीआई का एक उप गवर्नर और एक अधिकारी इस समिति के अन्य दो सदस्य होते हैं।
- एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति में करों को कम करना या सरकारी खर्च बढ़ाना शामिल है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करना है। आरबीआई की विस्तारवादी नीति में शामिल हैं
  - — वैधानिक तरलता अनुपात को कम करना।
  - — सीमान्त स्थायी सुविधा को कम करना और।
  - — बैंक दर और रेपो दर को कम करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक कार्य

साख का नियन्त्रण RBI का प्रधान कार्य है। साख के नियन्त्रण (मौद्रिक नीति के अन्तर्गत) से आशय साख विस्तार एवं संकुचन से है। वह सभी कार्य जो विश्व के अन्य देशों के केन्द्रीय बैंक करते हैं, उन सभी कार्यों को RBI भी करता है।

रिज़र्व बैंक साख के नियन्त्रण व नियमन हेतु दो प्रकार के उपायों का प्रयोग करता है—परिमाणात्मक साख नियन्त्रण एवं गुणात्मक साख नियन्त्रण।

परिमाणात्मक साख नियन्त्रण

रिज़र्व बैंक के साख के नियन्त्रण व नियमन हेतु परिमाणात्मक साख नियन्त्रण (Quantitative credit control) के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं

- **रेपो दर** इसका का अभिप्राय उस दर से है, जिस पर सार्वजनिक व निजी बैंक अपनी अल्प अवधि की आवश्यकताओं के लिए रिज़र्व बैंक से उधार लेते हैं। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो दर (Repo Rate) कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएँगे।
- **रिवर्स रेपो दर** जब बैंक अपनी अतिरिक्त राशि कुछ समय के लिए रिज़र्व बैंक के पास रखते हैं, तो इस अतिरिक्त राशि के लिए रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) पर ब्याज मिलता है, इस धन को पार्किंग भी कहा जाता है। आरबीआई तरलता प्रबन्धन के अन्तर्गत रेपो और रिवर्स रेपो का प्रयोग करता हैं। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अपने यहाँ धन जमा करने का लालच देता है। यह स्थिति भी मौद्रिक तरलता को कम करती है।
- **आधार दर** यह उधार देने की न्यूनतम दर है। RBI के निर्देशानुसार वाणिज्यिक बैंक इससे कम दर पर उधार नहीं दे सकते हैं। बेस रेट या आधार साख (Base Rate) बाज़ार में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए RBI द्वारा तय की जाती है। यह आरबीआई द्वारा वर्ष 2010 में लाई गई थी। आधार दर के स्थान पर अब सीमान्त विधि लागत पर आधारित उधार दर अस्तित्व में आ गई है।
- **बैंक दर** जिस दर पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों की प्रतिभूतियों पर ऋण देता है, उसे बैंक दर (Bank Rate) कहते हैं। बैंक दर में परिवर्तन करके RBI देश में साख की मात्रा को प्रभावित कर सकता है।
  व्यावहारिक अर्थों में वाणिज्यक बैंकों द्वारा आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण जिस ब्याज दर पर प्राप्त किया जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग है।
- **चलनिधि समायोजन सुविधा** आरबीआई द्वारा बैंकों को दी गई चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) एक महत्त्वपूर्ण सुविधा है। यह मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन में प्रयुक्त किया जाने वाला एक प्रमुख उपकरण है। इसके अन्तर्गत रेपो और रिवर्स आते हैं, जिनकी दरों पर

नियन्त्रण करके भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार में उपलब्ध मुद्रा को नियन्त्रित करता है।

- **मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटी रेट** मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत 9 मई, 2011 में हुई। मार्जनिल स्टैडिंग फैसिलिटी (Marginal Standing Facility) के अन्तर्गत RBI बैंकों के अति अल्पकालिक ऋण आवश्यकता की पूर्ति करता है। रिवर्स रेपो दर से यह हमेशा 1% अधिक होता है।
- **नकद आरक्षित अनुपात** अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाओं (Deposits) का कुछ निश्चित भाग रिज़र्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य किया गया है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio, CRR) कहा जाता है। इस अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक राशि रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित रखनी होती है। अत: उनके पास तरलता (नकद कोष) में कमी हो जाती है, जिसके चलते उनकी ऋण प्रदान करने की क्षमता में कमी आ जाती है।
- **सांविधिक तरलता अनुपात** बैंकों को अपने पास कुल जमाओं (Deposits) का कुछ अनुपात तरल रूप में (स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियाँ मुख्यत: सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में) रखना आवश्यक होता है, इसे सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio, SLR) कहते हैं। यह अनुपात 40% की सीमाओं में ही रखा जा सकता है। यह सुविधा जून, 2000 में पहली बार पेश की गई थी। बाद में वर्ष 2001 और 2004 में इसमें संशोधन किए गए थे।
- **खुले बाजार की क्रियाएँ** इसके द्वारा भी साख विनियमन का कार्य किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market Operations) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूति, बचत पत्र एवं विभिन्न बॉण्ड शामिल हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आरबीआई के सहयोग से सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार में जारी की जाती है, जिन्हें बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाता है। खुले बाजार की क्रिया (Open Market) अधिक होने से बाजार में साख के प्रवाह में कमी आती है।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत श्रेणियाँ हैं-कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य। 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार' (Priority Sector Lending, SLR) को आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों के रुचि के लिए लाया गया है।
- **बाजार स्थिरीकरण योजना** इस योजना के अन्तर्गत आरबीआई विदेशी मुद्रा को बाजार से खरीदकर या मुक्त कर विनिमय दर में स्थिरता लाती है। आरबीआई योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से बॉण्ड जारी करती हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना (Market Stabilisation Scheme) इसमें नीलामी विधि का प्रयोग होता है।
- **सीमान्त निधि लागत पर आधारित उधार दर** बैंकों के ऋण ब्याज पर तय करने के लिए इस नई विधि का प्रयोग किया जाता है। सीमान्त निधि लागत पर आधारित उधार दर (Marginal Cost of funds based Lender Rate) विधि से जहाँ उपभोक्ता को कम ब्याज दर का लाभ मिलेगा, वहीं बैंकों की पहले से ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। यह ब्याज दर की विधि 1 अप्रैल, 2016 से लागू हो गई हैं। इसने आधार दर प्रणाली का स्थान लिया है।

RBI द्वारा मुद्रास्फीति एवं विकास नियमन

RBI वृहद् स्तर पर अपने उपकरणों द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और विकास गतिविधियों का नियमन करता है। RBI मौद्रिक तरलता को संकुचित करने के लिए रेपो रेट और CRR को बढ़ा देता है, जिससे अर्थव्यवस्था में माँग कम हो जाती है और मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहती है।

गुणात्मक साख नियन्त्रण

जब रिज़र्व बैंक को यह प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदार साख नीति की आवश्यकता है, तो बैंक गुणात्मक/चयनात्मक साख नियन्त्रण (Qualitative or Selective Credit Control) व्यवस्था को अपनाता है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक सार्वजनिक हित में किसी भी बैंक को या एक साथ सभी बैंकों को ऋण सम्बन्धी निम्नलिखित निर्देश दे सकता है

- मूल्यान्तर निश्चित करने से सम्बन्धित निर्देश।
- ऋण देने सम्बन्धित (प्रतिबन्ध या पूर्वानुमति) निर्देश।

उद्देश्य

गुणात्मक/चयनात्मक साख नियन्त्रण की नीति मुख्यत: दो उद्देश्यों से अपनाई जाती है

- सट्टा व जमाखोरी रोकने हेतु
- मूल्यों में अनुचित वृद्धि रोकने हेतु

गुणात्मक नियन्त्रण के उपाय

गुणात्मक/चयनात्मक साख नियन्त्रण के उपाय निम्न हैं

- **ऋण की सीमान्त आवश्यकता में परिवर्तन** RBI ने सदस्य बैंकों को निर्देश दिया है कि वे समय-समय पर ऋण की सीमान्त आवश्यकता में परिवर्तन (Chang in Margin Requirements on Loans) करते रहें। प्रथम बार इस प्रकार का निर्देश RBI ने मई और सितम्बर, 1956 में दिया था।
- **ऋण की अधिकतम सीमा** RBI ने वाणिज्यिक बैंक के लिए ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। वर्ष 1965 में इस योजना के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1975 से यह व्यवस्था की गई कि किसी एक व्यक्ति या संस्था को ₹ 2 करोड़ या इससे अधिक राशि देने के पूर्व सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- **साख की राशनिंग** यह साख का गुणात्मक (Qualitative) नियन्त्रण करने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका है। साख की राशनिंग (Rationing of Credit) का उद्देश्य बैंकों की साख निर्माण शक्ति को सीमित करना है। अन्तिम ऋणदाता (Lender of the last resort) के रूप में केन्द्रीय बैंक जब अन्य बैंकों की माँग को पूर्णरूप से पूरा नहीं कर पाता, तो वह इसकी राशनिंग कर देता है अर्थात् यह निश्चित कर देता है कि प्रत्येक बैंक को कितनी साख दी जाएगी?
- **नैतिक दबाव** सामान्यत: व्यापारिक बैंक रिज़र्व बैंक की सलाह तथा निर्देश की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सलाह न मानने पर उन्हें हानि हो सकती है। नैतिक दबाव (Moral Persuation) व्यवस्था नैतिक प्रभाव के रूप में कार्य करती है। सीमान्त आवश्यकता उन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बढ़ जाती है, जिसके क्रेडिट का प्रवाह अर्थव्यवस्था में प्रतिबन्धित किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक के अन्य कार्य

परिमाणात्मक और गुणात्मक साख नियन्त्रण के अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया निम्नलिखित अन्य कार्य भी करता है

- **निर्यात उद्योग** रिज़र्व बैंक निर्यात उद्योगों को ऋण भी देता है। ये ऋण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में दिए जाते हैं।
- **समाशोधन गृह** बैंकों का बैंक होने के कारण रिज़र्व बैंक समाशोधन गृह (Clearing House) का कार्य भी करता है अर्थात् यह बैंकों के आपसी लेन-देन सम्बन्धित क्रियाकलापों का निपटान केन्द्र भी है।
- **मुद्रा परिवर्तन** बैंक बड़े नोटों के बदले छोटे नोट तथा छोटे नोटों के बदले सिक्के देने का कार्य भी करता है।
- **सूचना प्रकाशन** रिज़र्व बैंक मुद्रा, साख, वित्त, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करता है तथा उनके आधार पर बनी रिपोर्टों के प्रकाशन का भी दायित्व निभाता है। रिज़र्व बैंक का मासिक बुलेटिन महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएँ व आँकड़े भी देता है।

विदेशी विनिमय प्रबन्धन

- विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का प्रबन्धन भारतीय रिज़र्व बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रुपए के विदेशी मुद्राओं में विनिमय दर को भी नियन्त्रित करता है।
- यह अपनी नियामक गतिविधियों द्वारा विनिमय दर में सन्तुलन बनाए रखता है। इसके लिए वह विदेशी मुद्रा की माँग व पूर्ति को नियन्त्रित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक केवल उन्हीं देशों की मुद्राओं से व्यवहार करता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के सदस्य हैं।

रिज़र्व बैंक पर आवश्यक प्रतिषेध

- रिज़र्व बैंक की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु की गई है।
- यह न ही अचल सम्पत्ति की जमानत पर कर्ज़ दे सकता है और न ही ऐसी सम्पत्ति अपने उपयोग के लिए खरीद सकता है।
- यह बिना जमानत के कर्ज़ (Unsecured Loan) नहीं दे सकता।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio, CAR) वित्तीय संस्थानों की प्राथमिक पूँजी प्रतिशत अनुपात को (इसमें सम्पत्ति के अन्तर्गत ऋण तथा निवेश) वित्तीय मजबूती और स्थिरता के मापने के रूप में प्रयोग किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग सुधार के प्रमुख प्रयास

बेसल मानक

स्विट्जरलैण्ड के शहर बेसल में वर्ष 1980 में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के सन्दर्भ में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने कुछ मानदण्डों का निर्धारण किया। इन्हीं को **बेसल मानक** (Basel Norms) के नाम से जाना गया। बेसल मानदण्ड अन्तर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlement, BIS) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में (जून, 2021 के अनुसार) 63 देशों का केन्द्रीय बैंक बीआईएस के सदस्य हैं।

बेसल-I

यह मानक पहली बार वर्ष 1988 में घोषित किया गया। इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले वित्तीय संस्थानों को अपनी जोखिम सारांश सम्पदा के बराबर अथवा कुल पूँजी का न्यूतनतम 8% टायर I व टायर-II पूँजी अपने पास रखना अनिवार्य किया गया।

टायर-I एवं टायर-II पूँजी

(i) **टायर-I** पूँजी नियामक के दृष्टिकोण से वित्तीय शक्ति का कोड मापक है। सामान्य शेयर एवं घोषित कोष से टायर-II पूँजी बनती है। इसमें गैर-प्रतिदेय और गैर-संचयी शेयर शामिल नहीं होता है।

(ii) **टायर- II** यह अनुपूरक पूँजी होती है तथा टायर-II से कम विश्वसनीय होती है। इसमें बैंक पूँजी के महत्त्वपूर्ण और वैध घटक ही होते हैं।

बेसल-II मानक

बेसल के सम्मेलन वर्ष 1980 में हुए जिसमें बैंकों हेतु जो मानदण्ड निर्धारित किए गए वे मुख्यत: 'न्यूनतम पूँजी अपेक्षा' एवं 'ऋण जोखिम' से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2004 में पुन: बेसल-II मानकों का निर्धारण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटना था। बेसल-II का उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अलग रखी जाने वाली पूँजी के लिए मानक तैयार करना व इसका विनियमन करना था।

बेसल-III मानक

बेसल-III मानक, भारत में अप्रैल, 2013 से लागू हो गए हैं, जो चरणबद्ध तरीके से मार्च, 2019 तक पूर्णरूप से लागू होना था, परन्तु कोविड के कारण अब जनवरी, 2023 से लागू हो जाएँगे। इसके लिए भारत सरकार ने बैंकों के पूँजी आधार में वृद्धि हेतु समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है।

बेसल-III के मुख्य प्रावधान

बेसल III मानदण्डो के अन्तर्गत मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं

- बैंक अपने कोर टियर I पूँजी अनुपात को बढ़ाकर 4.5% करेंगे।
- प्रतिचक्रीय पूँजी का प्रावधान 2.5% का संरक्षण बफर 2019 (अब 2023) तक करना।
- जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात (Capital to Risk Assets Ratio, CRAR) के लिए आवश्यक कुल पूँजी बेसल III के लिए 10.5% के लिए प्रस्तावित है।

बेसल-III के लिए नियम

बेसल III के लिए RBI के दिशा-निर्देश 2 मई, 2012 को जारी किए गए, जो इस प्रकार हैं

- चालू आधार पर भारत के बैंक टायर-I पूँजी और कोर पूँजी न्यूनतम 7% होनी चाहिए।
- कुल पूँजी अनुपात (टायर-I + टायर-II) 9% अवश्य होना चाहिए।
- पूँजी अनुपात को 31 मार्च, 2013 तक सभी बैंक भारत में RBI के दिशा-निर्देश के अनुसार जारी किया।

बेसल तृतीय दिशा-निर्देश फ्रेमवर्क 2015

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 मई, 2015 को बैंकों के लिए तरलता मानक पर बेसल तृतीय फ्रेमवर्क के अन्तर्गत स्थिर अनुदान अनुपात (Net Stable Funding Ratio, NSFR) पर दिशा-निर्देश जारी किया।
- देश के सभी बैंक अपनी परिसम्पत्तियों और बैलेन्स शीट से सम्बन्धित मामलों में वित्तीय स्थिति को स्थिर रख सकें, इसी उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी बैंकों में नेट स्थिर अनुदान अनुपात को 1 जनवरी, 2018 से लागू करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब वर्ष 2023 तक का प्रस्ताव है।
- बेसल समिति ने वित्त पोषण तरलता के लिए तरलता कवरेज़ अनुपात और नेट स्थिर अनुदान अनुपात दो अलग न्यूनतम मानक, लेकिन पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए। RBI द्वारा जनवरी, 2015 से ही तरलता कवरेज अनुपात का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया।

प्रश्न बैंक

1. निम्नलिखित में से किस वर्ष हिल्टन यंग कमीशन द्वारा सर्वप्रथम रिज़र्व बैंक के गठन का प्रस्ताव रखा गया?
(a) वर्ष 1923 (b) वर्ष 1925
(c) वर्ष 1927 (d) वर्ष 1929
(e) वर्ष 1931

2. देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षक है
(a) केन्द्रीय बैंक (b) व्यापक बैंक
(c) स्टेट बैंक (d) ये सभी
(e) इनमें से कोई नहीं

3. किस वर्ष बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1949 बैंकिंग विनियमन अधिनियम में तब्दील हो गया?
(a) वर्ष 1963 (b) वर्ष 1964
(c) वर्ष 1965 (d) वर्ष 1966
(e) वर्ष 1967

4. भारतीय रिज़र्व बैंक है **[RBI Assistant 2013]**
(a) वित्त मन्त्रालय के तहत केन्द्र सरकार का एक विभाग
(b) एक निकाय कॉर्पोरेट, सतत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर
(c) भारतीय बैंक संघ के स्वामित्व वाली एक संस्था
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

5. कौन-सा सिद्धान्त केन्द्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धान्तों में सम्मिलित नहीं है? **[SBI Clerk 2012]**
(a) मुद्रा चलन का अधिकार
(b) जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएँ
(c) मौद्रिक नीति-निर्धारक
(d) साख-नियन्त्रण
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

6. अर्द्धवार्षिक आधार पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? **[RBI Grade B 2015]**
(a) भारतीय रिज़र्व बैंक
(b) विश्व आर्थिक मंच
(c) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(d) नीति आयोग
(e) वर्ल्ड बैंक

7. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का वित्तीय वर्ष होता है **[RBI Grade B]**
(a) 1 अप्रैल से 31 मार्च
(b) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर
(c) 1 सितम्बर से 31 अगस्त
(d) 1 जुलाई से 30 जून
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

8. भारतीय रिज़र्व बैंक में कितने उप-गवर्नर होते हैं?
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5
(e) 6

9. भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित में से किस पूर्व गवर्नर ने केन्द्रीय वित्तमन्त्री के रूप में भी कार्य किया है? **[RBI Grade B 2015]**
(a) डॉ. सी. रंगराजन (b) एल. के. झा
(c) बी वेकटरमन (d) डॉ. आईजी पटेल
(e) सी.डी. देशमुख

10. भारतीय रिज़र्व बैंक के 22वें गवर्नर कौन थें? **[SBI Clerk 2012]**
(a) डॉ. के. सी. चक्रवर्ती (b) डॉ. डी. सुब्बाराव
(c) डॉ. वी. वाई. रेड्डी (d) डॉ. एस. गोकर्ण
(e) इनमें से कोई नहीं

11. निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं?
(a) श्री पी. चिदम्बरम (b) श्री यशवन्त सिन्हा
(c) श्री प्रणब मुखर्जी (d) श्री मनमोहन सिंह
(e) इनमें से कोई नहीं

12. आरबीआई को अन्तिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि **[IBPS Clerk 2015]**
(a) इसे उन नागरिकों की ऋण आवश्यकता को पूरा करना है, जिन्हें कोई और उधार देने को तैयार नहीं है
(b) बैंक अन्तिम उपाय के रूप में आरबीआई को उधार देते हैं
(c) यह संकट के समय बैंकों की मदद करने के लिए आता है
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

13. आरबीआई के क्षेत्रीय मामलों का नेतृत्व व संचालन करता है **[IBPS Clerk 2015]**
(a) केन्द्रीय बोर्ड (b) स्थानीय बोर्ड
(c) क्षेत्रीय बोर्ड (d) ये सभी
(e) इनमें से कोई नहीं

14. आरबीआई केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को दिन-प्रतिदिन की प्राप्ति और व्यय बेमेल को पूरा करने के लिए ············ प्रदान करता है। **[IBPS Clerk 2015]**
(a) ट्रेजरी बिल
(b) तरीके और साधन अग्रिम
(c) तारीख और प्रतिभूतियाँ
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान, एक संस्था है **[SBI Clerk 2014]**
(a) विकल्प के रूप में दिए गए सभी
(b) बैंक को प्रबन्धन कर्मी प्रदान करना
(c) बैंकिंग में बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण
(d) बैंक प्रबन्धन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर परामर्श प्रदान करना
(e) सभी स्तरों पर बैंक कर्मचारियों की भर्ती

16. 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेण्ट' का क्या कार्य है? **[IBPS Clerk 2012]**
(a) बैंकों को मैनेजमेण्ट कर्मचारी उपलब्ध कराना
(b) बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना
(c) बैंक मैनेजमेण्ट की श्रेष्ठ विधियों पर सलाह उपलब्ध कराना
(d) सभी स्तर के बैंक कर्मचारियों की नियुक्ति कराना
(e) उपरोक्त सभी

17. भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली से सम्बन्धित विजन-2018 हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? **[IBPS PO 2016]**
(a) वित्त मन्त्रालय (b) नीति आयोग
(c) वाणिज्य मन्त्रालय (d) भारतीय रिज़र्व बैंक
(e) इनमें से कोई नहीं

18. मौद्रिक नीति सम्बन्धित है **[SBI Clerk 2015]**
(a) मुद्रा पूर्ति से (b) मुद्रा की माँग से
(c) साख की माँग से (d) साख की पूर्ति से
(e) मुद्रा एवं साख पूर्ति से

19. कौन-सी विधि परिमाणात्मक नियन्त्रण के परिक्षेत्र में नहीं आती?
(a) बैंक दर
(b) तरल कोषानुपात
(c) साख सम्भाजन
(d) परिवर्तनशाली न्यूनतम कोषानुपात
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

20. भारतीय रिज़र्व बैंक की उस निर्देशात्मक पॉलिसी दर को क्या कहते हैं, जो ब्याज दरों पर लम्बी अवधि के दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है? **[SBI PO 2014]**
(a) बैंक दर
(b) रेपो दर
(c) कॉल मनी दर
(d) नोटिस मनी दर
(e) रिवर्स रेपो दर

21. निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में से एक है? **[SBI Clerk 2015]**
(a) शेयर बाजारों का विनियमन
(b) जीवन बीमा विनियमन
(c) सामान्य बीमा का विनियमन
(d) भारत में म्यूचुअल फण्ड का विनियमन
(e) बैंकर्स बैंक

22. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाए गए क्रेडिट नियन्त्रण के निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण क्रेडिट नियन्त्रण के सामान्य या मात्रात्मक तरीकों के अन्तर्गत नहीं आता है? **[IBPS Clerk 2015]**
(a) बैंक दर
(b) खुले बाजार का संचालन
(c) निर्दिष्ट वस्तुओं पर अग्रिम के सम्बन्ध में कुछ न्यूनतम मार्जिन (सीमान्त) की शर्तें
(d) परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकताएँ
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. बैंक दर नीति, खुले बाजार संचालन, परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकताएँ और क्रेडिट नियन्त्रण के उपायों के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा नियोजित वैधानिक तरलता आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया गया है **[IBPS PO 2011]**
(a) मात्रात्मक विधि (b) गुणात्मक विधि
(c) मौद्रिक विधि (d) ये सभी
(e) इनमें से कोई नहीं

24. भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्पूंजीकरण का कार्यक्रम चलाया है, जो उन्हें व्यापार वृद्धि और ········· में मदद करेगा। **[SBI PO 2014]**

(a) पूँजी पर्याप्तता मानदण्ड
(b) गैर-निष्पादित सम्पत्तियों का अनुपात
(c) प्रति कर्मचारी व्यापार अनुपात
(d) सीएएसए अनुपात
(e) क्रेडिट या जमा अनुपात

25. आरबीआई नीति दर जो विशुद्ध रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सांकेतिक दर है **[SBI PO 2014]**

(a) बैंक दर (b) रेपो दर
(c) कॉल मनी दर (d) नोटिस मनी दर
(e) रिवर्स रेपो दर

26. भारत में बैंकों को अपनी माँग और सावधि देनदारियों का एक हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखता है, जिसे कहते हैं **[SBI PO 2013]**

(a) वैधानिक तरलता अनुपात
(b) नकद आरक्षित अनुपात
(c) बैंक जमा
(d) रिवर्स रेपो
(e) सरकारी प्रतिभूतियाँ

27. बैंकों में आधार दर है **[IBPS Clerk 2011]**

(a) माँग जमा पर देय ब्याज दर
(b) सावधि जमा पर देय ब्याज दर
(c) आरबीआई द्वारा दीर्घकालिक उधार पर ब्याज की दर
(d) आरबीआई द्वारा तय की गई न्यूनतम उधारी दर, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अपनाई जाएगी
(e) व्यक्तिगत बैंकों द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर, जिसके नीचे वे सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जैसे मामलों को छोड़कर धन उधार नहीं दे सकते

28. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में निर्दिष्ट राशि नकद और नकद समकक्षों में रखी जाती है और बैंक वॉल्ट में संग्रहीत की जाती है **[SBI PO 2014]**

(a) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
(b) भारत सरकार
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक
(d) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
(e) ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास फण्ड

29. जिस ब्याज दर से कम पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार नहीं दिया जाता है, कहलाता है **[SBI PO 2013, RBI Grade B-2015]**

(a) डिपॉजिट रेट (b) बेस रेट
(c) प्राइम लैण्डिंग रेट (d) बैंक रेट
(e) डिस्काउण्ट रेट

30. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई, 2012 से उधार दरों की गणना के लिए अन्तरण/विनियम करने की सलाह दी है **[IBPS PO 2013]**

(a) एमएसएफ दर प्रणाली
(b) रिवर्स रेपो दर प्रणाली
(c) बैंक दर प्रणाली
(d) रेपो दर प्रणाली
(e) बेस दर प्रणाली

31. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) निम्नलिखित में से किस उद्योग/बाजार से सबसे निकट रूप से सम्बन्धित है? **[IBPS Clerk 2011]**

(a) पूँजी बाजार (b) बैंकिंग उद्योग
(c) कमोडिटी बाजार (d) मुद्रा बाजार
(e) म्यूचुअल फण्ड उद्योग

32. रेपो रेट क्या है? **[IBPS Clerk 2011]**

(a) यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है
(b) यह वह दर है जिस पर आरबीआई बाजार में छोटे ऋण की अनुमति देता है
(c) यह वह दर है जिस पर बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं
(d) यह वह दर है जो बैंकों द्वारा अपने सबसे प्रमुख ग्राहकों को दी जाती है
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

33. बाजार की तरलता को नियन्त्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किस साधन का उपयोग किया जाता है?

(a) रेपो दर **[SBI PO 2014]**
(b) वैधानिक तरलता अनुपात
(c) सीमान्त समायोजन सुविधा
(d) रिवर्स रेपो रेट
(e) 'a' और 'd' दोनों

34. आरबीआई बाजार की तरलता को कैसे मापता है?

(a) रिवर्स रेपो रेट (b) रेपो रेट
(c) नकद आरक्षित अनुपात (d) वैधानिक तरलता अनुपात
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

35. आधार दर वह दर है, जिससे कम पर कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? **[IBPS PO/MT 2012, RBI Grade B 2015]**

(a) व्यक्तिगत बैंक, बोर्ड (b) वाणिज्य मन्त्रालय
(c) वित्त मन्त्रालय (d) आरबीआई
(e) इनमें से कोई नहीं

36. रिवर्स रेपो आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है **[IBPS RRB Main 2017]**

(a) बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने
(b) तरलता अवशोषित करना/कम करना
(c) इंजेक्ट लिक्विडिटी (तरलता)
(d) तरलता को एक स्तर पर रखना
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

37. वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? **IBPS Clerk 2013**

(a) यह अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा प्रवाह को कम करता है
(b) इसे केवल नकदी के रूप में बनाए रखा जाता है
(c) यह सेकिंग सिस्टम में तरलता को नियन्त्रित करता है
(d) यह वाणिज्यिक बैंकों की करदान क्षमता सुनिश्चित नहीं करता है।
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

38. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात किस रूप में रखा जाता है? **[IBPS Clerk 2013]**

(a) न्यूनतम नकद भण्डार (b) स्वर्ण
(c) स्वीकृत प्रतिभूतियाँ (d) 'a' तथा 'b'
(e) ये सभी

39. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) ग्राहकों की कुल जमा राशि का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को किसी देश के केन्द्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। सीआरआर नियन्त्रण **[SBI PO Main 2016]**

(a) बैंकों के लिए पैसा उधार लेना सस्ता है
(b) एक उपकरण है जिसका उपयोग केन्द्रीय बैंक अल्पकालिक उद्देश्य के लिए करता है
(c) मुद्रा आपूर्ति पर केन्द्रीय बैंक का अधिक नियन्त्रण
(d) विभिन्न नीतिगत दरों को अलग-अलग अंशांकित करने के पुराने तरीके से हटकर विपणन करना
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

40. नकद आरक्षित अनुपात क्या है? **[IBPS PO Main 2016]**

(a) बैंकों में जमा सरकारी प्रतिभूमियाँ
(b) वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन लेता है
(c) नकद, जिसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है
(d) वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है
(e) वह दर जिस पर आरबीआई सरकार से पैसा उधार लेता है

41. संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता बफर के रूप में कार्य करने वाले भण्डार हैं **[IBPS Clerk 2011]**

(a) 0 सीएआर
(b) 0 सीआरआर
(c) सीएआर और सीआरआर
(d) सीआरआर और एसएलआर
(e) एसएलआर

42. निम्नलिखित में से किस तन्त्र के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता का अन्त:क्षेपण किया जाता है? **[SBI Clerk 2014]**

(a) बैंक दर में परिवर्तन (b) रेपो
(c) एसएनआर में वृद्धि (d) तरलता समायोजन सुविधा
(e) सीआरआर में वृद्धि

43. भारतीय रिज़र्व बैंक प्रारम्भिक वर्षों में तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों के साथ होम लोन उत्पादों की आलोचना कर रहा है, लेकिन बाद के वर्षों में उच्चतर है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जाना जाता है **[SBI PO 2014]**

(a) टीजर रेट (b) चीटर रेट
(c) ट्विस्टर रेट (d) चीपर रेट
(e) ट्रिक्सटर रेट

44. आरबीआई द्वारा सीआरआर (CRR) में वृद्धि, की ओर ले जाती है **[IBPS Clerk 2015]**

(a) जमा में कमी
(b) जमा में वृद्धि
(c) उधार देने योग्य संसधानों में वृद्धि
(d) उधार देने योग्य संसाधनों में कमी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

45. सीआरआर (CRR) फण्ड बैंकों द्वारा रखे जाते हैं **[IBPS Clerk 2015]**

(a) शाखाओं में नकद
(b) अन्य बैंकों के साथ शेष
(c) आरबीआई के साथ एक विशेष खाते में शेष
(d) मुद्रा तिजोरी में धन
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

46. एसएलआर (SLR) प्रतिशत के रूप में बनाए रखा जाता है **IBPS Clerk 2015]**
(a) समय देनदारियाँ
(b) माँग की देनदारियाँ
(c) 'a' तथा 'b'
(d) सकल समय और माँग की देयताएँ
(e) शुद्ध माँग और समय की प्रयोगशाला

47. भारतीय रिज़र्व बैंक तय नहीं करता है
(a) रेपो और रिवर्स रेपो की दरें
(b) सीमान्त स्थायी सुविधा दर
(c) बैंक दर
(d) सरकारी कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की दर
(e) सांविधिक तरलता अनुपात

48. केन्द्रीय बैंक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण निम्न में से किस दर पर देता है? **[IBPS PO 2011]**
(a) रेपो दर (b) रिवर्स रेपो दर
(c) बैंक दर (d) SLR
(e) CRR

49. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को सलाह दी कि वह अपना बटुआ खोले और खर्च करे। इससे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? **[IBPS PO 2011]**
I. बाजार में चलनिधि का संकट कम होगा।
II. इससे बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण कम लेंगे।
III. मुद्रास्फीति में कमी आएगी।
कूट
(a) I और II (b) केवल II
(c) II और III (d) I, II और III
(e) इनमें से कोई नहीं

50. ········· में भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्यालय नहीं है। **[Union Bank PO 2011]**
(a) कानपुर (b) जयपुर
(c) लखनऊ (d) भोपाल
(e) गुलबर्ग

51. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य नहीं करता है? **[IBPS PO 2012]**
(a) भारत में बैंकों का विनियमन
(b) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विनियमन
(c) भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन
(d) मुद्रा आपूर्ति का नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण
(e) भारत में मुद्रा प्रबन्धन

52. रेपो दर बढ़ाए जाने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव देखा जा सकता है **[IBPS PO 2012]**
(a) ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज दर महँगी होगी
(b) औद्योगिक उत्पादन कुछ हद तक प्रभावित होगा
(c) बैंक जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाएँगे
(d) औद्योगिक गृह विदेशों से धन उधार ले सकते हैं
(e) उपरोक्त सभी

53. RBI की मौद्रिक नीति के सम्बन्ध में प्राय: प्रयुक्त 'LAF' में 'L' अक्षर से क्या शब्द बनता है? **[IBPS PO 2011]**
(a) Liquidity (b) Liability
(c) Leveraged (d) Longitudinal
(e) Linear

54. भारत में बिलों की पुनर्भुनाई कर विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर को ········· कहते हैं। **[IBPS PO 2011]**
(a) विनिमय दर (b) सांविधिक चलनिधि अनुपात
(c) ब्याज दर (d) बैंक दर
(e) नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात

55. RBI रिवर्स रेपो नामक साधन का प्रयोग ······· के लिए करता है। **[IBPS PO 2011]**
(a) नकदी डालने
(b) नकदी निकालने
(c) बैंकिंग व्यवस्था में नकदी बढ़ाने
(d) नकदी को एक स्तर पर रखने
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

56. सरकार या RBI द्वारा मुद्रास्फीति के नियन्त्रण के लिए अपनाया जाने वाला उपाय निम्न में से कौन-सा नहीं है? **[IBPS PO 2011]**
(a) मौद्रिक नीति
(b) राजकोषीय नीति
(c) सार्वजनिक वितरण प्रणाली
(d) मूल्य नियन्त्रण
(e) वित्तीय समावेश

57. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है?
(a) मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है
(b) मुद्रा आपूर्ति घट जाती है
(c) मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है
(d) ब्याज दर अप्रभावी रहती है
(e) मुद्रा आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है

58. निम्नलिखिम में से कौन भारतीय रिज़र्व बैंक की मात्रात्मक ऋण नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत आते हैं?
(a) मार्जिन आवश्यकताएँ (b) नैतिक दबाव
(c) बैंक दर (d) RBI दिशा-निर्देश
(e) प्रत्यक्ष कार्यवाही

59. बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि
(a) देश की आर्थिक व्यवस्था लोचपूर्ण हो
(b) देश की आर्थिक व्यवस्था पूर्णत: बेलोच हो
(c) देश की आर्थिक व्यवस्था बेलोच हो
(d) 'b' और 'c'
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

60. बैंक दर में परिवर्तन के प्रभावों में सम्मिलित है
(a) साख संकुचन एवं प्रसार
(b) आन्तरिक कीमत स्तर का परिवर्तन
(c) विदेशी पूँजी प्रवाह में परिवर्तन
(d) उपरोक्त सभी
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

61. संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरिक्षित धन बतौर सफर चलनिधि काम कर सकती हैं, वे हैं
(a) CAR (b) CRR
(c) CAR और CRR (d) CRR और SLR
(e) SLR

62. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) पदों का अत्यधिक करीब से सम्बन्ध निम्नलिखित में से किस उद्योग/बाजार से है?
(a) पूँजी बाजार (b) बैंकिंग उद्योग
(c) कमोडिटी बाजार (d) मुद्रा बाजार
(e) म्यूचुअल फण्ड उद्योग

63. निम्न में से किस दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेते हैं?
[IBPS PO 2015, IBPS RRBs 2020]
(a) बैंक दर (b) सांविधिक तलरता अनुपात
(c) CRR (d) रेपो दर
(e) रिवर्स देपो दर

64. बैंक द्वारा उधारकर्ता को जिस ब्याज दर से नीचे उधार दिया जाना अपेक्षित नहीं होता है, उसे ······ कहते हैं।
[RBI Grade B 2015]
(a) जमा दर (b) आधार दर
(c) मूल उधार दर (d) बैंक दर
(e) डिस्काउण्ट दर

65. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के रूप में विनिर्दिष्ट राशि नकद या नकद-तुल्य होती है। यह बैंक वोलेट में रखी जाती है या इसके संरक्षण में होती है
[SBI PO 2013]
(a) सिडबी (b) भारत सरकार
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक (d) भारतीय स्टेट बैंक
(e) रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट फण्ड

66. भारत में बैंकों को अपनी माँग व सावधि देयताओं के एक हिस्से को भारतीय रिज़र्व बैंक में रखना पड़ता है। इस हिस्से को कहते हैं **[SBI PO 2013]**
(a) सांविधिक चलनिधि अनुपात
(b) आरक्षित नकदी निधि अनुपात
(c) बैंक जमा
(d) रिवर्स रेपो
(e) सरकारी प्रतिभूतियाँ

67. निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था में 'तरलता' को अन्तर्वेशित किया है?
(a) बैंक दर में बदलाव **[IBPS PO 2013]**
(b) रेपो
(c) SLR में वृद्धि
(d) लिक्विडिटी एडजस्टमेण्ट फेसिलिटी द्वारा
(e) CRR में वृद्धि

68. साख नियन्त्रण की कौन-सी नीति अर्थव्यवस्था में साख की माँग को अधिक प्रभावित करती है?
(a) बैंक दर नीति
(b) खुले बाजार की क्रियाएँ
(c) परिवर्तनशील कोषानुपात
(d) न्यूनतम कोषानुपात
(e) उपरोक्त सभी

69. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है?
(a) बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है
(b) ब्याज दर घट जाती है
(c) निजी क्षेत्र पर ऋण की मात्रा बढ़ जाती है
(d) बैंकों की आय बढ़ जाती है
(e) विदेशी पूँजी प्रवाह में परिवर्तन नहीं होता है

70. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है?
(a) भुगतान सन्तुलन (b) बैंक गारण्टी
(c) अमानत राशि (d) नकद आरक्षित अनुपात
(e) बैंक ऋण

71. निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है?

(a) केन्द्रीय बैंक, बैंक दर, व्यापारिक बैंक दर और बाज़ार दर निर्धारित करते हैं
(b) केन्द्रीय बैंक, बाजार दर और व्यापारिक बैंक दर निर्धारित करते हैं
(c) बैंक दर और बाज़ार दर समानर्थी हैं
(d) बैंक दर और बाज़ार दर का कोई सम्बन्ध नहीं है
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

72. मुद्रास्फीति के नियन्त्रण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग में लिया जा रहा, सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है

(a) ब्याज दरें बढ़ाना
(b) ब्याज दरें कम करना
(c) मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना
(d) मुद्रा आपूर्ति कम करना
(e) ब्याज दर बढ़ाना और मुद्रा आपूर्ति कम करना

73. वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio) में वृद्धि का परिणाम होता है

(a) बैंकों के पास कम नकदी
(b) सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति
(c) बैंकों की लाभदायकता में कमी
(d) 'a' और 'b'
(e) 'a', 'b' और 'c'

74. बैंक दर में वृद्धि सामान्यत: इस बात का संकेत है कि

(a) ब्याज की बाजार दर के गिरने की सम्भावना है
(b) केन्द्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा
(c) केन्द्रीय बैंक सस्ती नीति का अनुसरण कर रहा है
(d) केन्द्रीय बैंक महँगी मुद्रा-नीति का अनुसरण कर रहा है
(e) ब्याज की दर को बढ़ाकर केन्द्रीय बैंक सस्ती मुद्रा-नीति अनुसरण कर रहा है

75. निम्नलिखित में से कौन-सा 'रेपो दर' का सही अर्थ दर्शाता है?

(a) वह दर जिस पर RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है
(b) बैंक द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर
(c) बैंकों द्वारा अपने महत्त्वपूर्ण ग्राहकों को ऑफर की गई दर
(d) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण देने के लिए लागू दर
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

76. निम्नलिखित में से किस सुविधा के तहत वाणिज्यिक बैंक RBI से ओवरनाइट ऋण ले सकते हैं? **[SBI PO 2014]**

(a) CRR (b) SLR (c) MSF (d) CDR
(e) इनमें से कोई नहीं

77. बैंकों को आरक्षित नकदी का जो अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक में रखना पड़ता है, उसे ……… कहते हैं। **[RBI Grade B 2012]**

(a) नकद आरक्षित अनुपात
(b) चलनिधि अनुपात
(c) निवल माँग और सावधि देयता
(d) सांविधिक तरलता अनुपात
(e) उपरोक्त में से कोई नहीं

78. सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

I. SLR के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा निर्धारित अनुपात के बराबर अपनी जमा की अपने पास नकदी रखनी होती है।
II. यह वित्तीय कम्पनियों को न्यूनतम आरक्षितियाँ रखने के लिए बाध्य करने की एक विधि है।
III. इसके तहत म्यूचुअल फण्डों के लिए लाभांश के रूप में एक न्यूनतम राशि की घोषणा करना जरूरी है।
IV. यह RBI द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) I और II
(b) I और III
(c) II और III
(d) I और IV
(e) I, II, III और IV

79. ब्याज और चलनिधि के प्रबन्ध का RBI का नीतिगत उद्देश्य है

(a) मुद्रास्फीति नियन्त्रित करना और आर्थिक विकास बनाए रखना
(b) निजी और सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के बीच प्रतियोगिता नियन्त्रित करना
(c) सरकारी क्षेत्र में बेरोजगारी मिटाना
(d) जनता के हाथों में मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण
(e) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशियों का नियन्त्रण

80. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गुणात्मक/चयनात्मक साख नियन्त्रण के उपाय हैं

(a) ऋण की सीमान्त आवश्यकता में परिवर्तन
(b) ऋण की अधिकतम सीमा
(c) साख की राशनिंग
(d) 'b' तथा 'c'
(e) 'a' 'b' तथा 'c'